घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 41- गुरूवार 11- दिसम्बर 2025,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये ,www.ghatati-ghatana.com,RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2023-2025

संक्षिप्त समाचार

शशि थरूर ने वीर सावरकर अवॉर्ड लेने से इनकार किया...

नई दिल्ली,10 दिसम्बर 2025। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में वीर सावरकर अवॉर्ड को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया। उन्होंने कहा...मैं ये अवॉर्ड लेने नहीं जा रहा हूं। मुझे इसके बारे में केरल में रहते हुए मीडिया रिपोर्ट्स से ही जानकारी मिली। कांग्रेस सांसद ने कहा कि आयोजकों ने बिना पूछे मेरा नाम घोषित किया है। ऐसे में दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं, अवॉर्ड देने वाले एनजीओ ने थरूर के दावे को गलत बताया। दि हिंगरेज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया के संस्थापक अजी कृष्णन ने दावा किया कि वे एक महीने पहले थरूर से उनके घर पर मिले थे। थरूर ने अवॉर्ड स्वीकार करने की सहमति दी थी। दो हफ्ते पहले भी जूरी चेयरमैन रवि कांत ने उनसे मुलाकात की थी। दरअसल, बुधवार को दिल्ली में 'वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड 2025' आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता शशि थरूर को भी ये अवॉर्ड देने की घोषणा की गई है।

इंडिगो संकट : स्पाइसजेट हर रोज 100 अतिरिक्त फ्लाइट्स करेगा शुरु

नई दिल्ली,10 दिसम्बर 2025। इंडिगो संकट के बीच स्पाइसजेट एयरलाइन ने मौजूदा सर्दियों के मौसम में प्रमुख रूटों पर बढ़ती मांग को देखते हुए अपनी सेवाओं को बढ़ाने की योजना बनाई है। इसका मकसद भारतीय विमानन बाजार में पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करना है। इस कोशिश के चलते स्पाइसजेट ने नियामक अनुमोदन के अंतर्गत मौजूदा विंटर शेड्यूल के दौरान हर रोज 100 अतिरिक्त फ्लाइट्स शुरू करने की योजना बनाई है। पिछले दो महीनों में,एयरलाइन ने 17 विमानों को अपने एक्टिव ऑपरेशन में शामिल किया है। यह विस्तार डैम्प-लीज पर लिए गए विमानों और अपने खुद के विमानों को सेवा में वापस लाने के जरिए किया गया है। इस बढ़ी हुई मांग से स्पाइसजेट को ज्यादा मांग वाले रूटों पर अतिरिक्त क्षमता तैनात करने में मदद मिलेगी। स्पाइसजेट ने कहा है कि वह सर्दियों में मजबूत और बढ़ती मांग को देख रही है।

दिवाली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया

पीएम मोदी बोले...दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा

नई दिल्ली,10 दिसम्बर 2025। यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया। यूनेस्को ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन की इंटैन्जिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त विश्व धरोहर की सूची जारी की। इसमें घाना, जॉर्जिया, कांगो, इथियोपिया और मिस्र सहित कई देशों के सांस्कृतिक प्रतीक भी शामिल हैं। इस पर पीएम मोदी ने कहा,'दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा है।'

भारत की 15 अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। इसमें दुर्गा पूजा,कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार,रामलीला,छाऊ नृत्य भी शामिल हैं। ये फैसला उस समय आया है, जब दिल्ली में यूनेस्को की इंटर-गवर्नमेंटल कमेटी फॉर इंटैन्जिबल हेरिटेज की 20 वीं बैठक की मेजबानी कर रही है। यह 8 से 13 दिसंबर तक चलेगी। इसी मौके को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 दिसंबर को विशेष दीपावली समारोह रखने का फैसला किया है,ताकि दुनिया के सामने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत तरह से पेश किया जा सके।

भारत की 15 धरोहरें पहले से लिस्ट में

यूनेस्को की यह लिस्ट दुनिया की ऐसी सांस्कृतिक और पारंपरिक चीजों को शामिल करती है,जिन्हें छू नहीं सकते लेकिन अनुभव किया जा सकता है। इसे अमूर्त विश्व धरोहर भी कहते हैं। इसका मकसद है कि ये सांस्कृतिक धरोहरें सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचें। फिलहाल, भारत की 15 धरोहरें पहले से अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में जगह बना चुकी हैं। इसमें दुर्गा पूजा, कुंभ मेला,वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला, छऊ नृत्य भी शामिल हैं।

मोदी बोले...दिवाली संस्कृति 3 और प्रकृति से जुड़ी

पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर बधाई देते हुए लिखा,'भारत और दुनियाभर के लोग उत्साहित हैं। हमारे लिए दिवाली,संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी है। यह हमारी सभ्यता की आत्मा है। यह ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने से इस त्योहार की वैश्विक लोकप्रियता में और भी वृद्धि होगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें शाश्वत रूप से मार्गदर्शन करते रहें।

कपिल मिश्रा बोले...सभी सरकारी इमारतें सजाई जाएंगी

दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि दिल्ली सरकार अलग से दिवाली मनाएगी। सभी सरकारी इमारतें सजाई जाएंगी, दिल्ली हाट में खास कार्यक्रम होंगे और लाल किले पर दीये जलाए जाएंगे। मंगलवार रात दिल्ली सचिवालय को तिरंगे रंगों की रोशनी से जगमगाया भी गया। सरकार का मकसद दीपावली को 'अंधकार से प्रकाश की ओर' ले जाने वाले वैश्विक संदेश के रूप में पेश करना है, ताकि यूनेस्को सूची में भारत का दावा और मजबूत हो सके। दिल्ली सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि वे शहरभर में हो रहे समारोहों में शामिल हों और मिलकर इस ऐतिहासिक पल को मनाएं। कार्यक्रम का मुख्य स्थान लाल किला होगा। यहां विदेशी मेहमान और देश के बड़े अधिकारी दीप जलाने की रस्म, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक कला के प्रदर्शन देखेंगे। राजधानी को सजाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को दी गई है। पूरे शहर में लाइटें लगाई जाएंगी, सजावट होगी, दीये जलाए जाएंगे और अलग-अलग जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे।

दीपावली का यूनेस्को की धरोहर में शामिल होना हर भारतीय के लिए गौरव : रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रकाश के उत्सव दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किए जाने को प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि हमारी हजारों वर्ष पुरानी सनातन परंपराओं की दिव्यता और सार्वभौमिकता को सर्वोच्च वैश्विक मंच पर मान्यता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान दीपावली के प्रकाश, सद्भाव और मर्यादा जैसे शाश्वत मूल्यों की वैश्विक स्वीकृति का प्रतीक है। दीपावली केवल एक उत्सव नहीं, अपितु वह आध्यात्मिक आलोक है जो सदियों से मानवता को सत्य, आशा और नैतिकता के पथ पर अग्रसर करता आया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस ऐतिहासिक निर्णय का पूरे हर्ष के साथ स्वागत करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के संकल्प को यह उपलब्धि और सशक्त बनाती है। योग, कुंभ, दुर्गा पूजा और गरबा जैसी हमारी सांस्कृतिक धरोहरों के बाद अब दीपावली को मिली यह वैश्विक मान्यता हमारी सांस्कृतिक यात्रा को और उज्ज्वल करती है। उन्होने यूनेस्को और हर उस परिवार, कारीगर और भक्त के प्रति कृतज्ञता, जिन्होंने प्रेम और निरंतरता के साथ इस परंपरा का पोषण किया है।

एमपी में पुलिस वैन-कंटेनर की भिड़ंत,4 जवानों की मौत

सागर,10 दिसम्बर 2025। सागर के नेशनल हाईवे-44 पर बांदरी के पास बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार कंटेनर और पुलिस के वाहन में आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में पुलिस वाहन में सवार 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसे एयरलिफ्ट कर दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं, टीम में शामिल डॉग सुरक्षित है। जानकारी के अनुसार मुरैना जिले का बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड बालाघाट में ड्यूटी पर तैनात था। पुलिसकर्मी नक्सल विरोधी अभियान में शामिल हुए थे। वहां से वे बीडी-डीएस वाहन (क्रमांक एम पी 03 ए 4883) में सवार होकर वापस मुरैना लौट रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे पर बांदरी के पास झिंझनी घाटी पर सामने से आ रहे कंटेनर से पुलिस वाहन की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डॉग मास्टर समेत चार जवानों की जान चली गई। कंटेनर और पुलिस वाहन की टक्कर इतनी भीषण थी कि ड्राइवर और जवान गाड़ी के अंदर ही फंस गए। पुलिस वाहन आगे से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जेसीबी की मदद से वाहन काटकर शवों को बाहर निकाला गया।

तिरुपति मंदिर में लड्डू के बाद दुपट्टा में घोटाला...सिल्क बताकर 350 के पॉलिएस्टर दुपट्टे 1300 में बेचे,10 साल में 54 करोड़ का स्कैम

तिरुपति,10 दिसम्बर 2025। आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डू के बाद प्रसाद के तौर पर दिए जाने वाले दुपट्टे (अंगवस्त्रम) की बिक्री में घोटाला सामने आया है। एक कॉन्ट्रैक्टर ने शुद्ध मुलबेरी सिल्क दुपट्टों की जगह लगातार 100% पॉलिएस्टर दुपट्टे सप्लाई किए। बिलिंग सिल्क दुपट्टों के नाम पर ही की गई। एक पॉलिएस्टर दुपट्टे की वास्तविक कीमत लगभग 350 थी। लेकिन,तिरुमला मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम् को वही 350 का दुपट्टा 1,300 में बेचा गया। ये घोटाला साल 2015 से 2025,यानी पिछले 10 साल से चल रहा था। इस दौरान TTD ने कॉन्ट्रैक्टर को लगभग 54 करोड़ भुगतान किए। TTD बोर्ड ने चेयरमैन बी.आर. नायडू के निर्देश पर एक इंटरनल जांच शुरू की गई थी, जिसके बाद पूरा मामला सामने आया।

लोकसभा में चुनाव सुधार और एसआईआर पर जमकर हंगामा

भाजपा के लोग चर्चा से नहीं भागते,विपक्ष एसआईआर पर झूठ फैला रहा,देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश : शाह

नई दिल्ली,10 दिसम्बर 2025। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को चुनाव सुधार पर कहा कि भाजपा के लोग चर्चा से नहीं भागते। विपक्ष एसआईआर पर विपक्ष झूठ फैला रहा है। देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। शाह ने कहा कि विपक्ष का काम हमको करना पड़ रहा है। चुनाव सुधार की जगह विपक्ष ने ज्यादातार बातें एसआईआर पर कीं। जैसी चर्चा की,अब मैं उस पर जवाब दे रहा हूं। एसआईआर पर विपक्ष ने 4 महीने से एक तरफा झूठ फैलाया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि एसआईआर वोट डिलीट करने का टूल बनकर रह गया है। चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने की अथॉरिटी नहीं है। चुनाव आयोग कह रहा है कि पांच लाख वोटर डिलीट, छह लाख वोटर डिलीट और बीजेपी जश्न मना रही है।

शाह बोले...चुनाव आयोग का गठन तब हुआ,जब हमारी पार्टी नहीं बनी थी

शाह ने कहा, मैंने एसआईआर का गहन अभ्यास किया है। कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया है। मैं उसका मेरे तर्कों से जवाब देना चाहता हूं। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। संविधान के अंदर आयोग का गठन,मतदाता की परिभाषा इसकी लिस्ट सुधार की शक्तियों का स्पष्ट प्रावधान संविधान में किए गए हैं। जब ये हुआ तब हमारी पार्टी नहीं बनी थी। इन लोगों ने ही इस पर चर्चा करके ये प्रावधान बनाए। आज की स्थिति में पर मैं जवाब दे रहा हूं। फ्री एंड फेयर चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है।

शाह बोले...विपक्ष ने एसआईआर पर एकतरफा झूठ फैलाया

अमित शाह ने कहा,चर्चा के लिए तय समय से ज्यादा समय लिया गया है। विपक्ष इसमें शामिल हुई। चुनाव सुधार की जगह विपक्ष ने ज्यादातार एसआईआर पर की।

जैसी चर्चा की। अब मैं उस पर जवाब दे रहा हूं। एसआईआर पर विपक्ष ने 4 महीने से एकतरफा झूठ फैलाया। जनता को गुमराह किया।

शाह ने कहा...एसआईआर पर नहीं,चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए तैयार

गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 दिन संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी। लोगों के बीच इस तरह का संदेश देने की कोशिश की गई कि हम चर्चा नहीं चाहते। हम बीजेपी और एनडीए के लोग डिबेट से कभी नहीं भागे। संसद सबसे बड़ी पंचायत है। चर्चा के लिए हमने ना कहा, इसके पीछे भी कारण थे। उन्होंने बताया कि विपक्ष की डिमांड थी एसआईआर पर चर्चा की। यह चुनाव आयोग का काम है। इस पर चर्चा होगी तो जवाब कौन देगा। जब ये चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए तैयार हुए, हमने दो दिन चर्चा की। अमित शाह ने कहा कि चर्चा तय हुई चुनाव सुधार पर, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने एसआईआर पर ही बोला। जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। मैंने पहले के भी सभी एसआईआर का गहन अध्ययन किया है और कांग्रेस की ओर से फैलाए गए झूठ का अपने तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है।

कंगना बोलीं...एक देश एक चुनाव लागू किया जाए...

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ये हर दिन एसआईआर,एसआईआर कर हंगामा कर रहे थे। दिल दहल जाता था इनको देखकर। कल राहुल गांधी जी जब बोल रहे थे, बार-बार वही खादी में धागा है, धागे से कपड़ा है,करते रहे।अंत में वह ले देकर विदेशी महिला की फोटो पर आ गए। वह खुद कई बार कह चुकी हैं कि कभी भारत नहीं गई हूं। उनकी तस्वीर का प्ले कार्ड में इस्तेमाल किया। उनके पर्सनालिटी राइट्स का भी ध्यान नहीं रखा। इसके लिए मैं संसद की तरफ से माफी मांगती हूं। ये ईवीएम हैक करने की बात करते हैं, भूल गए हैं कि प्रधानमंत्री दिलों को हैक करते हैं। कंगना ने राजनारायण बनाम इंदिरा केस का जिक्र करते हुए कहा कि ये धांधलियां इन्होंने की हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं छोड़ो पुरानी बातें। आपकी माता जी के पास जब नागरिकता नहीं थी, नागरिकता मिलने के कितने वर्षों पहले से वह वोट देती आई हैं। आपलोगों ने कभी भी इस देश की कानून-व्यवस्था का, संविधान का सम्मान नहीं किया हुआ है।

डिंपल यादव बोलीं...चुनाव आयोग सरकार के लिए काम कर रहा है

सपा की डिंपल यादव ने कहा...चुनाव आयोग को निष्पक्ष काम करना चाहिए लेकिन ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के लिए काम कर रहा है। यूपी चुनाव में बीजेपी ने मनमानी की लेकिन चुनाव आयोग ने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। आयोग पक्षपात कर रहा है। जबसे चुनाव आयुक्त चयन कमेटी में से सीजेआई को हटाया है तबसे ये ज्यादा हो रहा है। सरकार के लिए ही काम कर रहा है। एसआईआर के नाम पर नागरिकता कानून लागू किया जा रहा है। ये लोकतंत्र पर सीधा निशाना है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का रिविजन करता है।

प्रत्येक नागरिक की गरिमा और अधिकारों पर कोई समझौता नहीं हो सकता : राष्ट्रपति

नई दिल्ली,10दिसम्बर 2025। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रत्येक नागरिक की गरिमा और अधिकारों पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। भारत की सांस्कृतिक परंपरा वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत पर आधारित है, जो सार्वभौमिक मानवाधिकारों की भावना को मजबूत करती है। राजधानी दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन, आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन सारंगी, विजया भारती सयानी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा तथा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की समन्वयक अरेती सिएनी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर राष्ट्रपति मूमू ने आयोग के हिंदी जर्नल नई दिशाएं और अंग्रेजी जर्नल जर्नल आफ द एन एचआर सी का वर्ष 2024- 25 का संस्करण जारी किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत ने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसकी मूल भावना मानव गरिमा, समानता और स्वतंत्रता भारत की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने मानवाधिकार,लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को एक दूसरे से अविभाज्य बताया था। राष्ट्रपति ने कहा कि एनएचआरसी ने हाल के वर्षों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया है। आयोग 3000 से अधिक मामलों में स्वप्रेरणा से कार्यवाही कर चुका है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार और विकास परस्पर जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ पानी, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं सभी नागरिकों तक पहुंचाना मानवाधिकारों की पूर्ति का आधार है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और पीएम श्री स्कूल जैसे संस्थानों ने वंचित वर्गों के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई है। आवास और खाद्य सुरक्षा योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला है जिससे उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का आधार मिला है। उन्होंने कहा कि हाल के श्रम सुधारों और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों से श्रमिकों के अधिकार और सुदृढ़ हुए हैं।

सुदूर और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले सभी नागरिकों तक आवश्यक सुविधाएं पहुंचाना सरकार और समाज की साझा जिम्मेदारी है। समावेशी विकास का अर्थ है कि विकास की यात्रा में कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए।

रेपो रेट में कटौती का असर बैंकों ने सस्ते किए लोन ईएमआई में मिलेगी राहत

नई दिल्ली,10 दिसम्बर 2025। हाल ही में मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद लिए गए फैसले के तहत आरबीआई ने मुद्रास्फीति में कमी, मजबूत आर्थिक वृद्धि और संतोषजनक लिक्विडिटी स्थिति को देखते हुए रेपो रेट में कटौती जारी रखी है। इसका सीधा फायदा उधारकर्ताओं को मिल रहा है, क्योंकि लोन की ब्याज दरें घटने से आने वाले महीनों में EMI का बोझ कम होगा। 2025 में अब तक चार बार रेपो रेट में कटौती की जा चुकी है। फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट्स की पहली कटौती हुई थी। इसके बाद अप्रैल में फिर 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई। जून में मांग बढ़ने और सुधार के कारण 50 बेसिस पॉइंट्स की बड़ी कटौती की गई। अगस्त और अक्टूबर में कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि दिसंबर में चौथी बार 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की गई। इस तरह साल की शुरुआत से अब तक रेपो रेट में कुल 1.25 प्रतिशत की कमी हो चुकी है। रेपो रेट में हालिया कटौती के बाद कई सरकारी और निजी बैंकों ने भी अपने बेंचमार्क रेट घटाने शुरू कर दिए हैं।

भारत में 2027 की जनगणना होगी पूरी तरह डिजिटल,मोबाइल ऐप से होगा डेटा संग्रह

नई दिल्ली,10 दिसम्बर 2025। भारत में पहली बार 2027 की जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएगी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इसकी पुष्टि की है। इस जनगणना में डेटा मोबाइल ऐप के जरिए एकत्र किया जाएगा और यह भारत की 16वीं जनगणना होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत को दुनिया की सबसे तेज और आधुनिक डिजिटल जनगणना का नया मानक स्थापित करने में मदद करेगा। डिजिटल जनगणना दो चरणों में होगी। पहला चरण घर सूचीकरण और हाउस मैपिंग का होगा, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। दूसरा चरण जनसंख्या गणना का होगा, जो फरवरी-मार्च 2027 में किया जाएगा। इस प्रक्रिया में गणनाकारक (इनुमरेटर) कागज के फॉर्म के बजाय स्मार्टफोन ऐप का इस्तेमाल करेंगे। जनता भी स्वयं-जनगणना (सेल्फ-इनुमरेशन) कर सकेगी। ऐप 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा और कनेक्टिविटी समस्या वाले क्षेत्रों के लिए कागजी फॉर्म का बैकअप रखा जाएगा।

डिजिटल प्रक्रिया के कई फायदे हैं। यह पारंपरिक कागज आधारित प्रक्रिया की धीमी गति और त्रुटियों को दूर कर सकती है। प्रारंभिक आंकड़े 10 दिनों में और अंतिम आंकड़े 6-9 महीनों में उपलब्ध होंगे।

वन्यजीव संरक्षण के लिए अनंत को मिला ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड,यह सम्मान पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई

वाशिंगटन,10दिसम्बर 2025। अमेरिका में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय समारोह में वन्यजीव संरक्षण और पशु कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अनंत अंबानी को प्रतिष्ठित 'ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवॉर्ड' प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें उनके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'वनतारा' के माध्यम से घायल, बीमार और संकटग्रस्त जानवरों के बचाव, उपचार, पुनर्वास और संरक्षण में निभाई गई नेतृत्वकारी भूमिका के लिए दिया गया। इस उपलब्धि के साथ अनंत अंबानी इस अवॉर्ड को प्राप्त करने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई व्यक्ति बन गए हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इससे पहले यह सम्मान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और बिल क्लिंटन सहित कई वैश्विक नेताओं और चर्चित हस्तियों को मिल चुका है। अनंत अंबानी को मिले इस अवॉर्ड ने एक बार फिर 'वनतारा' को अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा का केंद्र बना दिया है।

संपादकीय

यौन उत्पीड़न के मामले में संवेदनशील बनें कोर्ट

सिस्टम की कमी और भाषा पर ध्यान देने की जरूरत

यौन अपराधों के मामलों में अदालतों की असंवेदनशील टिप्पणियों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर सकती है,क्योंकि ऐसी टिप्पणियां पीड़िता और उसके परिवार की गरिमा को आहत करती हैं और न्याय की लड़ाई को कमजोर करती हैं। यौन अपराधों के केस में अदालतों की असंवेदनशील टिप्पणियों का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जिसकी जरूरत भी थी। दरअसल, सुनवाई के दौरान अदालती टिप्पणी केवल कागजों में दर्ज शब्द नहीं रह जाती,इसका पीड़िता और उसके परिवार पर व्यापक असर पड़ता है। कई बार न्याय की लड़ाई भी कमजोर होती है इससे। इस साल मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी आई थी,जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वह हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता इसलिए जायज है,क्योंकि इस तरह की टिप्पणियां बार-बार सामने आ रही हैं। यहां तक कि मौजूदा केस शुरू होने के बाद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इसी तरह के मामले हुए। यौन अपराधों को केवल कानून नहीं, मानवीय नजर से भी देखे जाने की जरूरत है। पीडिता और उसका परिवार पहले ही गहरे मानसिक संघर्ष से गुजर रहे होते हैं। ज्यादातर मामलों में समाज का भी दबाव होता है। ऐसे में जब अदालतों से असंवेदनशील कमेंट्स आते हैं, तो पीड़िता और उनके परिवार की गरिमा आहत होती है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से कानून की व्याख्या की थी, उससे बचा जा सकता था। महिलाओं के साथ होने वाला अपराध केवल कानून की व्याख्या तक सीमित नहीं है। अदालतों से निकली हर बात समाज पर गहरा असर छोड़ती है। इनका इस्तेमाल अपराध की गंभीरता को कम करने में भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि कई बार इन्हीं तरीकों से पीड़िता को शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर किया जाता है,न्याय तंत्र की खामी बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत की महिलाओं को सशक्त करने वाले कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। आधी आबादी को कार्यस्थलों पर मिली सुरक्षा हो, ट्रिपल तलाक से मुक्ति या फिर उत्तराधिकार में बराबरी का हक-देश की न्याय व्यवस्था ने महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। ऐसे में उसी के किन्हीं अंगों में महिलाओं से जुड़े मामलों के प्रति संवेदनहीनता ठीक नहीं। अब समय है, जब निचली अदालतें यह समझें कि यौन अपराधों से जुड़े मामलों में कानून की समझ के साथ भाषा और दृष्टिकोण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यही वक्त की मांग है।

नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मैक्स बॉर्न

संजय गोस्वामी
मुंबई,महाराष्ट्र

मैक्स बॉर्न का जन्म 11 दिसंबर,1882 को ब्रेस्लाउ में हुआ था। उनके पिता प्रोफेसर गुस्ताव बॉर्न थे,जो एनाटॉमिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। 11 दिसंबर, 1882 को ब्रेस्लाउ शहर में जन्मे मैक्स बॉर्न, एक उच्च-मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता,प्रोफ़ेसर गुस्ताव बॉर्न एक प्रतिष्ठित भ्रूणविज्ञानी थे, जो मानव शरीर और उसके विकास के अध्ययन में शामिल थे। उनकी माँ, मार्ग्रेट (नी कॉफ़मैन),एक प्रतिष्ठित सिले सियन उद्योगपति परिवार से थीं, जिसने मैक्स के पालन-पोषण के लिए एक ठोस सामाजिक और बौद्धिक आधार प्रदान किया। बचपन में,मैक्स का स्वास्थ्य नाजुक था, जिसके कारण शुरुआत में उन्हें निजी शिक्षकों द्वारा घर पर ही पढ़ाया गया, जिन्होंने उनकी जिज्ञासा और सीखने के प्रति प्रेम को पोषित किया। जैसे-जैसे वे बड़े हुए,उन्होंने औपचारिक शिक्षा ग्रहण की और ब्रेस्लाउ के प्रतिष्ठित कोनिग विल्हेम जिमनैजियम में दाखिला लिया। यहीं पर विज्ञान के प्रति उनका आकर्षण पनपने लगा और उन्होंने उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया। प्राकृतिक दुनिया को समझने में गहरी रुचि के कारण,मैक्स ने ब्रेस्लाउ, हीडलबर्ग, ज्यूरिख और गोटिंगेन सहित कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भौतिकी और गणित में उच्च शिक्षा प्राप्त की। प्रत्येक संस्थान ने एक वैज्ञानिक के रूप में उनके विकास में अद्वितीय योगदान दिया। गोटिंगेन में,प्रख्यात गणितज्ञ फेलिक्स क्लेन के मार्गदर्शन में, मैक्स ने 1906 में अपनी डॉक्टरेट थीसिस पूरी की, जो प्रत्यास्थ तारों की स्थिरता पर केंद्रित थी–एक ऐसा विषय जिसमें भौतिकी और गणित में उनकी रुचि का मेल था। उन्हें 1907 में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो उनके पेशेवर जीवन की शुरुआत थी। डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद, मैक्स ने कुछ समय के लिए सेना में सेवा की, यह एक ऐसा अनुभव था जो चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद,उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा नहीं बना। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जोसेफ लारमोर और जे.जे. थॉमसन जैसे प्रमुख भौतिकविदों के साथ काम किया और प्रायोगिक और सैद्धांतिक भौतिकी में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उनकी बौद्धिक जिज्ञासा उन्हें वापस ब्रेस्लाउ ले गई,जहाँ उन्होंने आइंस्टीन के विशिष्ट सापेक्षता के अभूतपूर्व सिद्धांत का अध्ययन करने में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। इस अन्वेषण ने उनके लिए नए क्षितिज खोले और अंततः गौटिंगेन में प्रतिष्ठित गणितज्ञ हरमन मिंकोव्स्की के साथ सहयोग स्थापित किया। उनके कार्य ने सापेक्षता के गणितीय औपचारिकतावाद के लिए महत्वपूर्ण आधार तैयार किया। 1912 में...मैक्स ने हेडविग एहरनबर्ग से विवाह किया, जिससे उन्हें व्यक्तिगत खुशी मिली, हालाँकि उनकी शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं के दबाव और पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने की चुनौतियों के कारण उनका रिश्ता अक्सर तनावपूर्ण रहा। उनके तीन बच्चे हुए। 1915 तक, एक भौतिक विज्ञानी के रूप में मैक्स बॉर्न की प्रतिष्ठा अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी, और उन्हें बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया, एक ऐसा पद जिसने उन्हें अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों को प्रभावित करने और अपने शोध को आगे बढ़ाने का अवसर दिया। अपने पूरे जीवन में,मैक्स बॉर्न के भौतिकी में योगदान और क्वांटम यांत्रिकी के विकास में उनकी भूमिका ने उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। एक नाजुक बचपन से एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद बनने तक की उनकी यात्रा समर्पण, और जिज्ञासा का उदाहरण है - मैक्स बॉर्न का वैज्ञानिक जीवन, समर्पण, दृढ़ता और अभूतपूर्व खोजों से भरा एक सफ़र, 1915 में शुरू हुआ। उस समय, उन्हें बर्लिन विश्व विद्यालय में प्रोफेसर (असाधारण) के पद पर नियुक्त किया गया था, यह पद विशेष रूप से प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक की सहायता के लिए बनाया गया था। बॉर्न की नियुक्ति सैद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र

में उनकी विलक्षण प्रतिभा और क्षमता का प्रमाण थी। हालाँकि, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने से यह आशाजनक शुरुआत जल्द ही बाधित हो गई। अपनी शैक्षणिक ज़िम्मेदारियों के बावजूद, बॉर्न को जर्मन सशस्त्र बलों में भर्ती किया गया,जहाँ उन्हें एक सैन्य वैज्ञानिक कार्यालय में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। उनके कर्तव्यों में ध्वनि परास सिद्धांत का विकास और अनुप्रयोग शामिल था, जो ध्वनि तरंगों का विश्लेषण करके दुश्मन के तोपखाने का पता लगाने की एक तकनीक थी। यह सैन्य सेवा,हालाँकि कठिन और गहन थी,उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा को कम नहीं कर पाई। अपनी सैन्य प्रतिबद्धताओं के बीच भी,बॉर्न ने क्रिस्टल सिद्धांत पर अपने अध्ययन के लिए समय निकाला। क्रिस्टल में परमाणु और आणविक व्यवस्थाओं में उनकी रुचि ने उन्हें इस विषय पर गहनता से काम करने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयासों की परिणति उनकी पहली महत्वपूर्ण पुस्तक, डायनामिक डेर क्रिस्टल गिटर (क्रिस्टल जालकों की गतिकी) के प्रकाशन में हुई। इस कार्य ने गोटिंगेन में किए गए उनके प्रारंभिक शोध को संश्लेषित किया और क्रिस्टल संरचनाओं का एक व्यापक विश्लेषण प्रदान किया। यह इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान बन गया और क्रिस्टल भौतिकी में भविष्य के अनुसंधानों की नींव रखी। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, बॉर्न के करियर ने एक नई दिशा ली। उन्हें फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त किया गया, जहाँ उनके नाम पर एक समर्पित प्रयोगशाला स्थापित की गई। इस सुविधा ने उन्हें अपने शोध और शिक्षण गतिविधियों का विस्तार करने का अवसर दिया। फ्रैंकफर्ट में, उनके उल्लेखनीय सहायकों में से एक ओटो स्टर्न थे, जिन्होंने परमाणु और आणविक भौतिकी में प्रयोग किए। स्टर्न के प्रयोगों, जिनमें परमाणु किरणों के गुणों का पता लगाया गया था, ने अंततः उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिलाया,जिसने बॉर्न के मार्गदर्शन की उत्कृष्टता और उनकी प्रयोगशाला में किए गए शोध की गुणवत्ता को उजागर किया। 1921 में,बॉर्न वैज्ञानिक अनुसंधान के एक प्रतिष्ठित केंद्र, गोटिंगेन चले गए, जहाँ उन्होंने भौतिक विज्ञानी जेम्स फ्रैंक के साथ सहयोग किया। वे गोटिंगेन में बारह वर्षों तक फलदायी रहे। इस अवधि के दौरान, बॉर्न का वैज्ञानिक कार्य प्रचुर मात्रा में रहा। उन्होंने क्रिस्टल जालकों पर अपनी पिछली पुस्तक का पुन रावलोकन और संशोधन किया,अपने सिद्धांतों को परिष्कृत किया और उसके दायरे का विस्तार किया। साथ ही, उन्होंने क्वांटम सिद्धांत के उभरते क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। वोल्फगैंग पाउली, वर्नर हाइजेनबर्ग, पास्कुअल जॉर्डन, एनरिको फर्मी और पॉल डिराक जैसे प्रमुख भौतिकविदों के साथ उनके सहयोग ने सैद्धांतिक भौतिकी के एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। इस अवधि की एक उल्लेखनीय उपलब्धि 1925-26 में हाइजेनबर्ग और जॉर्डन के साथ क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर अन्वेषण नामक पुस्तक के प्रकाशन में,सहयोग था। यह कार्य क्वांटम यांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित करने में सहायक रहा। इसके अलावा, बॉर्न ने क्वांटम यांत्रिकी की सांख्यिकीय व्याख्या के विकास में योगदान दिया, जिसने परमाणु पैमाने पर कणों के व्यवहार को समझने का एक नया तरीका प्रदान किया। उनके अग्रणी प्रयासों ने बाद की कई खोजों की नींव रखी और अपने युग के अग्रणी भौतिकविदों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को सुदृढ़ किया।1936 में उन्हें एडिनबर्ग में प्राकृतिक दर्शन का प्रोफेसर नियुक्त किया गया,जहाँ उन्होंने 1953 तक काम किया। वह अब छोटे स्पा शहर, बैड पिरमोंट में रह रहे थे ।

मैक्स बॉर्न को कई अकादमियों-गोटिंगेन, मॉस्को, बर्लिन, बैंगलोर, बुखारेस्ट, एडिनबर्ग, लंदन, लीमा, डब्लिन, कोपेनहेगन, स्टॉकहोम,वाशिंगटन और बोस्टन की फेलोशिप से सम्मानित किया गया,और उन्हें ब्रिस्टल, बोर्डो,ऑक्सफोर्ड,फ्रीबर्ग/ब्रेइसगौ, एडिनबर्ग,ओस्लो, ब्रूसेल्स विश्व विद्यालयों, हम्बोल्ट विश्व विद्यालय बर्लिन और तकनीकी विश्वविद्यालय स्टटगार्ट से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई । उनके पास कैम्ब्रिज का स्टोक्स पदक,मैक्स प्लैंक मेडेल डेर ड्यूशेन फिजिकलिसचेन गेसेलशाफ्ट (यानी जर्मन फिजिकल सोसाइटी का) उन्हें रॉयल सोसाइटी, लंदन का ह्यूजेस मेडल, इंटरनेशनल लॉ के लिए ह्यूगो ग्रोटियस मेडल मिला, और उन्हें रॉयल सोसाइटी, एडिनबर्ग का मैकडॉगल-ब्रिस्बेन प्राइज़ और गनिंग-विक्टोरिया जुबली प्राइज़ भी मिला। 1953 में उन्हें गोटिंगेन शहर का ऑनरेरी नागरिक बनाया गया और एक साल बाद उन्हें फ़िज़िक्स के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। 1925 में, बॉर्न और वर्नर हाइज़ेनबर्ग ने क्वांटम मैकेनिक्स का मैट्रिक्स मैकेनिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाया। अगले साल, उन्होंने श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन बनाया, जिसके लिए उन्हें 1954 में नोबेल प्राइज़ दिया गया।उन्हें 1959 में जर्मन फ़ेडरल रिपब्लिक के ऑर्डर ऑफ़ मेरिट के स्टार के साथ ग्रैंड क्रॉस ऑफ़ मेरिट से सम्मानित किया गया। मैक्स बॉर्न क्वांटम मैकेनिक्स खासकर वेवफंक्शन के उनके स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन के लिए, जिसके लिए उन्हें 1954 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, जिससे यह साबित हुआ कि क्वांटम इवेंट्स प्रोबे बिलिस्टिक होते हैं, डिटरमिनिस्टिक नहीं। उन्होंने हाइजेनबर्ग के साथ मिलकर और ओपेनहाइमर जैसे भविष्य के बड़े लोगों को गाइड करके इस फील्ड को काफी हद तक बदला, और सॉलिड-स्टेट फिजिक्स, ऑप्टिक्स और रिलेटिविटी में योगदान दिया।उनकी मौत 5 जनवरी, 1970 को वेस्ट जर्मनी (अब जर्मनी) के गोटिंगेन में हुई थी। मैक्स बॉर्न, नोबेल प्राइज़ जीतने वाले फ़िज़िसिस्ट जो आज भी क्वांटम मैकेनिक्स में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। मैक्स बॉर्न ऐसे गुण जो उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को भी परिभाषित करते हैं।

मूल्य आधारित सफलता के संयम, कठोर श्रम और संकल्प मूल आधार

संजीव ठाकुर
रायपुर,छत्तीसगढ़

श्रेष्ठ ध्येय की प्राप्ति के लिए चिंता नहीं, चिंतन के साथ कठोर श्रम की आवश्यकता होती है। निराशा और चिंता मनुष्य की प्रगति के सबसे बड़े अवरोध हैं,ये मन के पंख काट देती

हैं और व्यक्ति को स्थिर कर देती हैं। आवश्यकता है कि निराशा को तत्काल विचारों से अलग किया जाए और चिंता को मन में प्रवेश न करने दिया जाए,अन्यथा अत्यधिक चिंता व्यक्ति को चिता तक ले जाने में देर नहीं लगाती। सकारात्मक सोच, नवीन संकल्प,दृढ़ निश्चय और संयम के साथ आगे बढ़ना ही सफलता का सार मार्ग है। मन में यदि संकल्प दृढ़ हो जाए तो संघर्ष की हर आँधी को जिजीविषा की शक्ति से मोड़ा जा सकता है।

कठिन कार्यों को जीवन में पहले चुनना चाहिए, क्योंकि कड़ी चुनौती ही ऊर्जा,सामर्थ्य और इच्छाशक्ति की परीक्षा लेकर मनुष्य को असाधारण बनाती है। कठिनाइयों से घबराकर उनसे पलायन करना निराशा को जन्म देता है,और निराशा से बढ़कर कोई बाधा नहीं होती, इसलिए हताशा को त्यागें, उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें सफलता स्वयं आपके चरण चूमेगी। समाज में जो महान व्यक्ति विलक्षण रूप में हमारे सामने खड़े हैं–जिनको आज की भाषा में सेलिब्रिटी कहा जाता है,उनकी चमक के पीछे अनवरत श्रम, अदम्य मानसिक शक्ति,संयम और अटूट विश्वास छिपा होता है। बड़ी सफलता का कोई सरल उपाय या शॉर्टकट नहीं होता है।लेकिन कठिन परिस्थितियाँ ही मनुष्य की दृढ़ता को तेज करती हैं और संघर्ष उसे मंज़िल के करीब ले जाता है। मानव जीवन में इच्छाएँ, आकांक्षाएँ और प्रयत्न स्वाभाविक हैं, किंतु सफलता कभी भी मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मूल्यहीन सफलता समाज के लिए संकट बन सकती है। यदि वैज्ञानिक अपनी क्षमता का उपयोग मानव कल्याण के लिए न करके जैविक या रासायनिक हथियारों के निर्माण में करे, तो वह प्रज्ञा विनाश में परिवर्तित हो जाती है यही कारण है कि सफलता के पीछे मानवीय मूल्य होना अनिवार्य है। मूल्य, सिद्धांत और नैतिकता ही लक्ष्य की पवित्रता और उपलब्धि की स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं। सफलता केवल स्थापित मापदंड नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण से जुड़ी होनी चाहिए।

विश्व की सभी सभ्यताओं, संस्कृतियों और धर्मों में सत्य, अहिंसा, दया, सेवा, करुणा और विश्व बंधुत्व जैसे गुणों की स्पष्ट स्वीकृति दिखाई देती है, और इन्हीं आधारों पर वैश्विक विकास की अवधारणा निर्मित होती है। भारत की सांस्कृतिक परंपरा में आदर्शों की प्रतिबद्धता स्वर्णिम धरोहर रही है। ऋषि-मुनियों से लेकर संत-परंपरा और स्वतंत्रता संग्राम के महापुरुषों तक–कबीर,रैदास, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, चिश्ती, औलिया, रहीम, खुसरो, गांधी, नेहरू, टैगोर, विवेकानंद और सुभाषचंद्र बोस, इन सबने मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा को ही श्रेष्ठ सफलता माना और अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दिया। सफलता का अर्थ केवल उपलब्धि नहीं बल्कि सत्य का सम्मान और करुणा की सेवा है। बिना मूल्यों की सफलता पानी की पतली धारा की तरह होती है, जो नदी का रूप नहीं ले सकती। राजनीति और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में तो मूल्यों का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण संवेदना, न्याय, कर्तव्य और नैतिकता के आधार पर ही संभव होता है। मूल्यहीन शासन समाज को विभाजन, भ्रम और अव्यवस्था की ओर धकेल देता है। राष्ट्र अपनी ही जड़ों को खोकर विखंडन की कगार पर पहुंच जाता है। सफलता तभी शाश्वत और स्थाई हो सकती है जब उसमें नैतिकता, सत्य, श्रम, संयम और मानवीय संवेदना का संगम हो। वही राष्ट्र दीर्घकालीन स्वतंत्र और सशक्त रह सकता है, जिसके नागरिक और नेतृत्वकर्ता मूल्यों, उसूलों और राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना के साथ कार्य करते हों। अंततः जीवन की सबसे बड़ी सफलता धन, पद या शोहरत नहीं, बल्कि वह आदर्श है जो हमारी पहचान को अमर बना देता है। चिरस्थाई सफलता का मार्ग केवल एक है निरंतर श्रम, अटूट संयम, सत्यनिष्ठ विचार और मानवीय मूल्य।

यूनीसेफ: बच्चों की शिक्षा,स्वास्थ्य,सुरक्षा एवं कल्याण को समर्पित संस्था

प्रमोद दीक्षित मलय
अतर्रा,बाँदा,उत्तर प्रदेश

द्वितीय विश्व युद्ध (वर्ष 1939 से 1945 तक) के बाद पूरी दुनिया में महिलाओं और बच्चों के लिए सामान्य मानवीय जीवन जीने की चुनौती उपस्थित हुई। भोजन एवं सुरक्षित आश्रय का बड़ा संकट खड़ा हुआ। बच्चों के लिए भोजन एवं आवास के साथ शिक्षा,स्वास्थ्य,सुरक्षा, समुचित पोषण और विकास के रास्ते पर रुकावटें एवं बाधाएं मुंह बाये खड़ी थीं। अधिकांश बच्चों के माता-पिता और परिवार युद्ध से प्रभावित हुए थे। बच्चों का जीवन कष्ट एवं पीड़ा के अंधेरे में सिसक रहा था, बालपन छिन गया था। बच्चों की स्वाभाविक निश्छलता, प्रसन्नता और अल्हड़ता गायब थी। बच्चे कुंठा, अवसाद और तनाव की काली चादर तले सहमते-सिसकते जीवन और मौत के पाटों के बीच अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे थे। चतुर्दिक नैराश्य और संवेदनहीनता का माहौल था। भूख, प्यास, दवा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति का कोई साधन दूर-दूर तक दृष्टिगोचर न था। कहीं से कोई मदद करने वाला नहीं,सहायता मिलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। तब एक आशा की किरण दिखाई दी। वर्ष 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघ ने बाल कल्याण के लिए एक संगठन बनाने का निर्णय लिया और 11 दिसम्बर, 1946 को संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष की स्थापना किया जो वर्तमान में 190 से अधिक देशों में यूनीसेफ के नाम से सामान्य मानवीय जरूरतों से वंचित एवं जोखिम उठा रहे बच्चों के समग्र विकास एवं कल्याण के लिए शिक्षा,स्वास्थ्य, सुरक्षा और पोषण प्रदान करने के विविध कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। तब से स्थापना दिवस 11 दिसम्बर को प्रत्येक वर्ष यूनीसेफ दिवस या बाल कल्याण कोष दिवस नाम से मनाते हुए यूनीसेफ द्वारा बच्चों की मदद के लिए किए गये महनीय योगदान को स्मरण किया जाता है। यूनीसेफ बाल अधिकारों की पैरवी करते हुए युद्ध एवं आपदा के समय आपातकालीन स्थितियों में भी अविलम्ब सहायता पहुंचाने को तत्पर रहता है। यूनीसेफ को दुनिया भर के बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य,शिक्षा एवं कल्याण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए वर्ष 1965 में नोबल शांति पुरस्कार, 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार तथा 2006 में प्रिंसेस आप आस्टु रियस पुरस्कार जैसे अंतरराष्ट्रीय

विख्यात एवं प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं।

भारत में यूनीसेफ ने वरू 1949 में केवल तीन कर्मचारियों के साथ काम करना आरंभ किया था और 1952 में नई दिल्ली में पहला कार्यालय खोला था। आज भारत के 16 से अधिक राज्यों में यूनीसेफ सरकारी विभागों एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिल कर बाल कल्याण के विविध कार्यक्रम चला रहा है। भारत सरकार द्वारा यूनीसेफ के साथ साझेदारी के 75 वर्ष पूरे होने पर 10 रुपए मूल्य का एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। इसके पूर्व 25वीं वर्षगांठ 1974, बाल अधिकार सम्मेलन की 30वीं वार्षिकी पर 1989 और एक अन्य अवसर पर 2009 में भी डाक टिकट जारी किए थे। वर्ष 1986 में यूनीसेफ गठन के 40 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीकाकरण एवं विकास निगरानी विषयक 50 पैसे एवं 5 रुपए के दो डाक टिकट जारी किए थे। निश्चित रूप से,यह भारत और यूनीसेफ के सम्बंधों की प्रगाढ़ता, गहराई और पारस्परिक समझ को दर्शाता है।

यूनीसेफ की भारत में बाल कल्याण की यात्रा 75 वर्ष से अधिक की हो गई है। इन वर्षों में यूनीसेफ ने सरकार, समुदाय और स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ मिलकर राष्ट्रीय टीकाकरण, जल स्वच्छता, शिशु मृत्यु दर में कमी, हिंसा एवं बाल यौन शोषण से बचाव, समुचित पोषण, आनंदमय गुणवत्ता परक शिक्षा, बाल अधिकारों का समर्थन एवं पैरवी तथा बाल कल्याण के अन्यान्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया है। हर बच्चे के जीवन का सबसे अच्छा आरम्भ हो और वह अपनी क्षमता अनुसार अपना पूर्ण विकास कर सके, इसके लिए यूनीसेफ उचित परिवेश निर्माण और जागरूकता के लिए सरकार एवं भागीदारों के साथ कार्यक्रम सुनिश्चित करता है। यूनीसेफ के कतिपय विशेष योगदान पर दृष्टिपात करें तो उत्साहजनक दृश्य दिखाई देता है। दुग्ध सहकारी संस्थाओं से बच्चों को रियायती दर पर दूध उपलब्ध कराने तथा दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापना हेतु 1954 में समझौता किया। इसी वर्ष मलेरिया उन्मूलन हेतु डीडीटी उत्पादन हेतु कारखाना निर्माण हेतु सहयोग किया। 1960 के दशक में विद्यालयों में रुचि पूर्ण विज्ञान शिक्षण हेतु तथा 1966 में सूखाग्रस्त बिहार के लोगों के लिए स्वच्छ सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार के साथ अनुबंध किया जो आगे चलकर ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम नाम से जाना गया। इसके अतिरिक्त टीकारण, राष्ट्रीय जनगणना, पोलियो मुक्ति अभियान को भी मदद दी। भारत की एक बड़ी सामाजिक समस्या खुले में शौच जाने की थी। यह बच्चों और महिलाओं के लिए शर्मनाक, अपमान जनक, अमानवीय और कष्टभरा दैनंदिन जरूरी कार्य था। वर्ष 2019 में खुले में शौच से मुक्ति का एक बड़ा अभियान चलाकर घर-घर शौचालय बनाने का काम सरकार के सहयोग से सम्पन्न हुआ। आज महिलाओ और बच्चों के लिए उनके मकान में या सहज पहुंच में ही शौच सुविधा उपलब्ध है। मानवता के लिए महासंकट कोविड के दौरान जीवन रक्षक दवाएं एवं उपकरण,आक्सीजन उत्पादन हेतु संयंत्र स्थापना तथा चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित मेडिकल संसाधन उपलब्ध करायें। यूनीसेफ के लिए भारत महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक अग्रणी और विश्वसनीय साझीदार है।

यूनीसेफ के स्थापना दिवस के अवसर पर हम सभी को यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि बच्चों की शिक्षा,सुरक्षा,स्वास्थ्य एवं विकास के लिए घर-परिवार, पड़ोस और कार्य स्थलों में सम्मानजनक स्थान बनाएंगे ताकि संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा घोषित बाल अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने में हम योगदान दे सकें। कह सकते हैं कि यूनीसेफ ने भारत के बाल कल्याण क्षेत्र में प्रतिष्ठित एवं उल्लेखनीय कार्य किया है। युद्धग्रस्त हिंसक दुनिया में हम बच्चों के लिए एक खुशियों भरी मुस्कुराती जगह बना सकें, जहां बच्चे अपना स्वाभाविक प्राकृतिक विकास कर सकें; यह संकल्प सिद्ध हो, ऐसी शुभेच्छा ।

देश को नीचा दिखातीं नियामक संस्थाएं

निजी क्षेत्र की कंपनियों पर कसनी होगी लगाम

राजीव सचान। बहुत दिन नहीं हुए जब विषाक्त कफ सीरप कोल्ड्रिफ के मामले में यह सामने आया था कि नियामक संस्थाओं ने अपना काम सही तरह नहीं किया। इस विषाक्त कफ सीरप के सेवन के चलते मध्य प्रदेश और राजस्थान में 25 से अधिक बच्चों की जान चली गई थी। देश में दवा निर्माण के लिए नियामक संस्था-केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएससीओ नियम तय करता है, पर कारखानों को लाइसेंस देने, दवा निर्माण इकाइयों के निरीक्षण और दवाओं के नमूनों का परीक्षण किए जाने जैसे काम राज्य औषधि नियामक प्राधिकरण करते हैं।राज्यों के ऐसे प्राधिकरणों की क्षमताएं अलग-अलग हैं और सीएसडीएओ के पास ऐसे अधिकार नहीं कि वह राज्यों के प्राधिकरणों के कामकाज की निगरानी रख सके। विषाक्त कफ सीरप से 25 बच्चों की मौतों के बाद ऐसी खबरें आईं कि दवा निर्माण एवं उनके परीक्षण की व्यवस्था को और सक्षम बनाया जाएगा, लेकिन कहना कठिन है कि ऐसा हो सकेगा और उसके नतीजे में कोल्ड्रिफ जैसे मामले फिर सामने नहीं आएंगे। कायदे से दवाओं के निर्माण की प्रक्रिया और उनकी गुणवत्ता की जांच-परख करने वाली संस्थाओं को सक्षम बनाने का बीड़ा तभी उठा लिया जाना चाहिए था, जब कुछ वर्ष पहले गांबिया और उज्बेकिस्तान में भारत में बनी कफ सीरप के सेवन से इन देशों के कई बच्चे मर गए थे।अपने देश में हर क्षेत्र के लिए नियामक संस्थाएं हैं, लेकिन यह प्रश्न अनुत्तरित है कि क्या वे पर्याप्त सक्षम हैं और अपना काम सही तरीके से कर पा रही हैं? ताजा मामला विमानन सेवाओं की नियामक संस्था डीजीसीए का है। इंडिगो एयरलाइन ने डीजीसीए के बनाए नियमों को लागू करने के स्थान पर उनकी अनदेखी करने का फैसला किया और वह भी तब, जब अन्य एयरलाइंस के साथ उसे भी इसके लिए करीब दो वर्ष का समय मिला था। अन्य एयरलाइंस ने तो डीजीसीए की ओर से पायलटों को आराम के घंटे बढ़ाने संबंधी नियमों पर अमल कर लिया, लेकिन इंडिगो ने ऐसा नहीं किया और वह भी तब जब अन्य एयरलाइंस घाटे में चल रही हैं और इंडिगो मुनाफे में।

किसी के घर जाओ तो
अपनी 'आंखो' को इतना काबू में रखो
कि उसके 'सत्कार' के अलावा
उसकी 'कमियां' न दिखे
और जब उसके घर से निकलो तो
अपनी 'जुबान' काबू में रखो ताकि उसके घर की
'इज्जत' और 'राज'
दोनो सलामत रहे। -आशीष गर्ग-

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

परसोढ़ी कला लाठीचार्ज व महिलाओं की गिरफ्तारी पर उच्चस्तरीय न्यायिक जांच और एफआईआर वापसी की मांग

भाजपा बेनकाब-ग्रामीणों पर लाठियां बरसाईं,अब घड़ियाली आंसू बहा रहे कांग्रेस नेता-आप

मानवाधिकार दिवस पर छत्तीसगढ़ बन चुका है मानवाधिकार उल्लंघन का मॉडल...जहां प्रदेश भर में किसानों व आदिवासियों की जमीन जबरन छीनी जा रही है,यह बर्दाश्त नहीं : प्रियंका शुक्ला

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 दिसम्बर 2025
(घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के ग्राम परसोढ़ीकला में भूमि अधिग्रहण के नाम पर सरकार की तरफ से पुलिस एवं प्रशासन द्वारा की गई बर्बर कार्रवाई लोकतंत्र के मूल्यों पर सीधा हमला है। आम आदमी पार्टी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती है और पीड़ित ग्रामीणों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जांच दल की अध्यक्ष प्रियंका शुक्ला के नेतृत्व में पार्टी के 10 सदस्यीय जांचदल ने परसोढ़ी कला गांव पहुंचकर पीड़ित महिलाओं व ग्रामीणों किसानों से भेंट मुलाकात की, ग्रामीण किसानों ने बताया कि 3 दिसंबर को बिना किसी पूर्व सूचना एसईसीएल एवं प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई शुरू की गई। मौके पर कलेक्टर सरगुजा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। शांतिपूर्ण भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे ग्रामीणों को धमकाते हुए कहा गया कि 15 मिनट में जो सोचना है सोच लो, नहीं तो हमको जो करना है करेंगे, इसके बाद ग्रामीणों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया। जांचदल के सामने प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, खेतों में काम कर रहीं महिलाओं के साथ अभद्रता कर उन्हें दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। आंदोलन में शामिल न होने वाले ग्रामीण जो खेती-बाड़ी और पशुपालन में लगे थे,उन्हें भी बेरहमी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। गांव के देवस्थान को क्षतिग्रस्त किया गया। घटना के दौरान खेतों से लोगों को भगाने के दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हुए। अफरा-तफरी में कई पशु बिछुड़ गए, जिनमें से 2-3 बकरियां अब तक लापता हैं। एक बकरी की मौत भी हुई है। घटना के बाद प्रशासन ने 7 महिलाओं सहित 10 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जो लोकतंत्र पर सीधा हमला है। ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में कहा कि वे अपनी एक इंच भी जमीन किसी भी कीमत पर एसईसीएल को नहीं देंगे,साथ ही स्थानीय विधायक-मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा मीडिया में दिए गए सहमति वाले बयान को ग्रामीण किसानों ने पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताया है। ग्रामीण पीड़ित किसानों ने बताया कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेजों को लेकर उन्होंने आरटीआई के माध्यम से एसडीएम उदयपुर और कलेक्टर सरगुजा कार्यालय से जानकारी मांगी थी, जिस पर दोनों कार्यालयों से लिखित जवाब मिला कि भूमि अधिग्रहण की कोई भी प्रक्रिया या दस्तावेज उनके अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद ग्रामीणों पर बलपूर्वक कार्रवाई करना प्रशासन की मनमानी व गैरकानूनी रवैये को उजागर करता है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि अमेरा परियोजना के पूर्व भूमि अधिग्रहण में एसईसीएल द्वारा कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। न रोजगार मिला,न उचित मुआवजा, और न ही किसी तरह का सीएसआर कार्य हुआ। जिन लोगों को नौकरी दी गई, उन्हें बाद में विभिन्न बहाने बनाकर निकाल दिया गया। इसी अनुभव के कारण ग्रामीण अब अपनी पुश्तैनी जमीन किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं हैं। जांचदल के सामने ग्रामीण किसान गोवर्धन जी ने बताया कि यह क्षेत्र भी पांचवी अनुसूचि के अंतर्गत आता है, ऐसे में जब जब अमेरा परियोजना के संबंध में हमसे सरकार द्वारा हमारे पंचायत का मत मांगा गया,तब तब हमारे द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से जमीन नहीं देंगे कहकर प्रस्ताव भी पारित करते हुए अपना मत शासन को बताया था, बावजूद इसके हमारी जमीन ली जा रही है। उक्त बात कई अन्य किसानों ने भी बताया , साथ ही गांव के विजय सिंह जिनकी उम्र 65 वर्ष लगभग थी, उन्होंने बताया कि वो घटना दिनांक को बकरी चरा रहे थे,घटना स्थल से आधा किलोमीटर दूर थे,बावजूद उसके करीब 4 बजे पुलिस वालो ने उनको लाठी से मारा, उनके साथ और भी लोगों को मारा जोकि घटना स्थल से दूर थे। गांव की किसान महिलाओं ने भी बताया कि महिलाओं के साथ बुरी तरह से दौड़कर मारपीट की गई है, जिससे सभी को चोट आई है। उसके बाद उल्टा एकतरफा गांव वालो पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जांच दल की अध्यक्ष अधिवक्ता प्रियंका शुक्ला ने कहा कि महिलाओं पर लाठीचार्ज करना, ग्रामीणों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटना, देवस्थान को नुकसान पहुंचाना और निर्दोष ग्रामीणों को जेल भेजना यह साबित करता है कि प्रशासन जनता का सेवक नहीं, बल्कि भाजपा सरकार और एसईसीएल के इशारे पर काम कर रहा है। ग्रामसभा की सहमति को नजरअंदाज कर जमीन छीनने का प्रयास लोकतंत्र और पेसा कानून दोनों का खुला उल्लंघन है। आम आदमी पार्टी पीड़ित ग्रामीणों के साथ मजबूती से खड़ी है और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। आज मानवधिकार दिवस पर सरकार को चेतावनी है कि छत्तीसगढ़ को मानवधिकार उल्लघंन का गढ़ बनने से रोकेज अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के राजीव लकड़ा ने कहा कि भाजपा द्वारा अमेरा खुली खदान को लेकर जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति भ्रामक है। भाजपा नेताओं ने ग्रामीणों के सहमति देने और समझौते हेतु बैठक में जाने का दावा किया, जबकि सच्चाई यह है कि ग्रामीण केवल अपने निर्दोष साथियों की रिहाई के लिए बातचीत करने गए थे, वहां जब यह लोग गए तो स्श्वष्टरु के अधिकारी भाजपा के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे इस बात की जानकारी ग्रामीणों को नहीं थी, ग्रामीणों द्वारा किसी भी प्रकार की सहमति नहीं दी गई। यह झूठ साबित करता है कि भाजपा नेता अब जनता के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि एसईसीएल के दलाल और प्रवक्ता बन चुके हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज दुबे ने कहा कि भाजपा सरकार पूरे प्रदेश में उद्योगपतियों के दबाव में काम कर रही है। मैनपाट भूमि अधिग्रहण, अमेरा खदान दमन और परसोढ़ी कला लाठीचार्ज उसी नीति का परिणाम हैं। पांचवी अनुसूची,पेशा कानून ग्राम सभा के के अधिकारों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है लोकसभा सचिव लव कुमार दुबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जैसे रायगढ़, मैनपाट, छुईखदान प्रस्तावित खदानों / परियोजनाओं का आम लोग विरोध कर रहे हैं, खदानों के नाम पर पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है,आम आदमी पार्टी इस अन्याय के विरुद्ध, संविधान के पक्ष में जनता के साथ डटी रहेगी।

आम आदमी पार्टी की मांगें...

1. परसोढ़ी कला लाठीचार्ज की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए।
2. निर्दोष ग्रामीणों पर दर्ज सभी एफआईआर तत्काल वापस ली जाएं।
3. प्रशासन कह रहा है कि कानूनी रूप से भूमि अधिग्रहण हुआ है यदि ऐसा है तो अधिग्रहण से संबंधित सारे दस्तावेज सार्वजनिक रूप से जारी किए जाएं।

इस जांचदल में में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला,अलेक्जेंडर केरकेट्टा,राजेंद्र बहादुर सिंह एवं मनोज दुबे,लोकसभा अध्यक्ष नरेंद्र नाग, लोकसभा सचिव लव कुमार दुबे,रामेश्वर विश्वकर्मा,अजय सिंह,राजेश गुप्ता,सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्मल स्कूल में जनजागरूकता कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य और बाल अधिकारों पर जोर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 दिसम्बर 2025
(घटती-घटना)।

कार्मल स्कूल में एक जनजागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया,जिसमें समाजसेवी शिल्पा पांडेय ने बाल अधिकार संरक्षण,मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन,महिला उत्पीड़न निवारण,नशे की प्रवृत्तियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। यह कार्यक्रम जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर विजन समाजसेवी संस्था द्वारा आयोजित किया गया। विजन समाजसेवी संस्था की निदेशक शिल्पा पांडेय ने इस अवसर पर बताया कि उच्चतम न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या और मानसिक स्वास्थ्य संकट को देखते हुए, हर शैक्षणिक संस्थान में मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए कार्यशालाओं, बैठकों, नाटकों और अन्य माध्यमों से जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए हैं। उनका उद्देश्य यह है कि जो बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हैं या जो 'रेड जोन' में हैं, उन्हें जीवन की प्रत्याशा में वापस लौटाया जा सके। शिल्पा पांडेय ने यह भी कहा कि वे लगातार शिक्षकों से संवाद स्थापित कर रही हैं और बच्चों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने के बाद महसूस हुआ कि बच्चों को एक समर्थन की आवश्यकता है। उनका मानना है कि छोटे प्रयास से माता-पिता के बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है। 'जीवन अनमोल है' यह जागरूकता की थीम जीवन के प्रति विश्वास और आस्था को पुनः स्थापित करने पर केंद्रित है। उन्होंने बच्चों से यह भी अपील की कि यदि उन्हें कहीं भी मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस होता है, तो वे सीधे संपर्क कर सकती हैं। समाजसेवी संतोष दास ने बच्चों के मानसिक विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, और बच्चों को जीवन की हर परीक्षा का सामना डटकर करना सिखाना चाहिए। कार्यक्रम का समापन कार्मल स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर रोशनी ने धन्यवाद ज्ञापन इस अवसर पर समाजसेविका अरुण सिंह ने भी अपने विचार साझा किए और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में विजन समाजसेवी संस्था के सदस्य राजू यादव, सुरेखा पैकरा, परमानंद गुप्ता और पीजी कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स भी उपस्थित थे।

बच्चों के लिए घर का वातावरण भी महत्वपूर्ण

कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के जिला मिशन प्रबंधक सर्वजीत पाठक ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए केवल स्कूल का वातावरण ही नहीं, बल्कि घर का वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि घर का माहौल तनावपूर्ण है, तो यह बच्चों को भीतर से कमजोर और डरपोक बना सकता है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों के संस्कारों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों का भविष्य उनके घर से ही बनता है।

अमेरा खदान विवाद को कांग्रेस का राजनीतिक रंग,भ्रम फैलाकर ग्रामीणों को भड़काने की कोशिश नाकाम होगी : सिसोदिया

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 दिसम्बर 2025
(घटती-घटना)।

लखनपुर अमेरा खुली खदान क्षेत्र की हालिया घटना को लेकर कांग्रेस से जुड़े कुछ स्थानीय नेताओं द्वारा लगातार राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से माहौल को राजनीतिक अखाड़े में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। सरल एवं भोले-भाले ग्रामीणों को तथ्यात्मक और विधि-सम्मत जानकारी देने के बजाय उन्हें भ्रमित कर उकसाने की कोशिश की गई, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। उक्त बातें कहते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि इस क्षेत्र का 2008 से 2023 तक विधायक और मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी. एस. सिंहदेव के कार्यकाल में यदि खदान को लेकर आपत्तियाँ थीं, तो उस समय खदान बंद कराने, कानूनों के विरुद्ध आवाज़ उठाने या पारित होने से रोकने जैसे कदम उठाए जाने चाहिए थे।उन्हीं के विधायक रहते हुए

अमेरा,परसोढ़ी कला एक्सटेंशन खदान का भूमि अधिग्रहण 2014 में हुआ और 2022 में कांग्रेस शासनकाल में कोल माइंस से जुड़े कुछ कानून पारित हुए–उस समय विरोध क्यों नहीं किया गया। भारत सिंह सिसोदिया ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस अधिग्रहण के खिलाफ है या कांग्रेस ग्रामीणों के मुआवजा या नौकरी की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस की गोलमोल बात समझ से परे है । कांग्रेस का यह दावा कि 'अचानक कार्रवाई की गई' का खंडन करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि अमेरा-परसोढ़ी कला प्रकरण पर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह भ्रामक,राजनीतिक रूप से प्रेरित और भूमि अधिग्रहण संबंधी वास्तविक कानूनी प्रक्रिया से असंगत हैं क्योंकि बिना पूर्व सूचना,ग्रामसभा की कार्यवाही, सामाजिक प्रभाव आंकलन आपत्तियों के निपटान और मुआवजा निर्धारण जैसी अनिवार्य प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना कोई भी अधिग्रहण संभव ही नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से महिलाओं पर पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप भी बिना किसी प्रमाण के है। जिला प्रशासन की प्रारंभिक रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि पुलिस बल केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूद था। श्री सिसोदिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने सदा से महिलाओं का सम्मान किया है,महिला उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, वहीं कांग्रेस द्वारा अमेरा विवाद में महिलाओं को बरगलाया जा रहा है, उन्हें फूल माला से सम्मानित करने का ढोंग करके हिंसा की भावना बढ़ाने का काम किया जा रहा है तो क्या कांग्रेस ग्रामीणों को माओवादी सोच के तरफ़ ले जाना चाहती है, शांतिपूर्ण तरीक़े से हल निकालने के विपरीत कांग्रेस की यह मानसिकता समाज के लिए ख़तरनाक है और शांतिपूर्ण वार्ता को हिंसक झड़प में बदलने के लिए कांग्रेस का दिग्भ्रमित नेतृत्व ज़िम्मेदार है। श्री सिसोदिया ने कहा कि मंत्री राजेश अग्रवाल का बयान पूरी तरह तथ्यों और दस्तावेज़ों पर आधारित है,कांग्रेस का यह कहना कि सहमति नहीं बनी, केवल राजनैतिक असंतोष भड़काने का तरीका है, मुद्दा विहीन कांग्रेस अपनी खोयी हुई जनाधार को झूठ और षड्यंत्र को आधार बना कर पाना चाहती है। भाजपा सरकार की नीतियों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासियों,किसानों और महिलाओं के अधिकारों की सबसे मजबूत संरक्षक है और उनके हितों की सुरक्षा हर परिस्थिति में सुनिश्चित की जाएगी।

अंबिकापुर में शीतलहर की स्थिति..कड़ाके की ठंड जारी,राहत की कोई उम्मीद नहीं

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 दिसम्बर 2025
(घटती-घटना)।

अंबिकापुर और आसपास के सरगुजा जिले में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड का कहर बरप रहा है। शीतलहर के चलते तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को भीषण सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान पिछले तीन-चार दिनों से करीब 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि पाट क्षेत्रों में यह और भी गिरकर 4 डिग्री तक पहुंच चुका है। खासकर बलरामपुर के सामरीपाट और सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र में ठंड की स्थिति बेहद खराब हो गई है, जहां जगह-जगह ओस की बूंदें भी जमने लगी हैं। इन इलाकों में सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव जलाने पर मजबूर हो गए हैं। मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने इस सर्दी के कारणों को स्पष्ट करते हुए बताया कि अंबिकापुर में तापमान लगातार गिर रहा है, लेकिन यहां कोहरे का असर नहीं है। इससे अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हो रही है। दिन में तेज धूप निकलने से भी ठंड का असर कुछ कम हो रहा है। हालांकि, वायुमंडल में नमी की कमी और उत्तर से शुष्क हवाओं के प्रभाव के कारण रात के समय ठंड में भारी बढ़ोतरी हो रही है। एसके मंडल के अनुसार, अगले 2-3 दिनों तक इस सर्दी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से 4 डिग्री के बीच बना रहेगा।

दिन में तापमान में हल्की वृद्धि

अंबिकापुर का अधिकतम तापमान मंगलवार को 26.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि वायुमंडल में नमी की कमी और आसमान के साफ रहने के कारण हुआ। हालांकि, दिन के दौरान तेज धूप के बावजूद ठंड का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, शुष्क हवाओं के कारण रात होते

ही ठंड में और अधिक वृद्धि हो जाती है,जिससे लोगों को अधिक परेशानी हो रही है। दिन में धूप के बावजूद रात के समय तापमान में भारी गिरावट आती है।

पाट क्षेत्रों में स्थिति गंभीर

अंबिकापुर के साथ-साथ पाट क्षेत्रों जैसे सामरीपाट और मैनपाट में ठंड का असर और भी ज्यादा है। यहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच चुका है, और इन क्षेत्रों में भी दिनभर ठंड का असर बना रहता है। स्थानीय लोग इस सर्दी से बेहाल हो गए हैं और ठंड से बचने के लिए अलाव जलाने पर मजबूर हो रहे हैं। इन इलाकों में खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर भी ठंड के चलते खासा प्रभावित हो रहे हैं, जिससे उनका दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है।

आने वाले दिनों में ठंड की स्थिति में सुधार की संभावना नहीं

मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक इस ठंड में कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, और ठंड की स्थिति बनी रहेगी। लोग इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए अधिकतर घरों में ही रह रहे हैं, जबकि सडक पर बाहर निकलते समय वे गर्म कपड़े पहनने के अलावा अलाव का सहारा भी ले रहे हैं।इस बीच, शीतलहर और शुष्क हवाओं का असर उत्तर भारत के कई अन्य हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है, जो इस क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का संकेत दे रहा है। आने वाले दिनों में मौसम और भी सर्द हो सकता है, जिससे ठंड की स्थिति और बढ़ सकती है।

अनफिट तोंद वाले पुलिसकर्मियों पर आईजी ने दिखाई सख्ती

सुबह-सुबह दौड़ लगाने का निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

किसी की तोंद बाहर है तो किसी को व्यसन की लत है,ऐसे में जब पुलिसकर्मी ही अनफिट रहेंगे तो भला इनसे फिट पुलिसिंग की उम्मीद कैसे की जाए। सरगुज़ा संभाग में ऐसे ही अनफिट पुलिस कर्मियों को फ़ीट करने की मुहिम शुरू की गई है ताकि पुलिस कर्मी खुद फ़ीट होकर बेहतर पुलिसिंग के साथ बेहतर जीवन जी सके। सुबह 4 बजे उठकर मैदान में पशीना बहाते और ट्रेनिंग लेते पुलिस के नव आरक्षक नही बल्कि वो पुलिस कर्मी है जो सालो से पुलिस विभाग में सेवा दे रहे है। इनमें आरक्षक, प्रधान आरक्षक से लेकर टीआई तक के पुलिस कर्मचारी,अधिकारी शामिल है, और ये सरगुज़ा संभाग के अलग-अलग जिलो में पदस्थ

अपनी सेवाएं दे रहे है। दरअसल सरगुज़ा संभाग के आईजी दीपक झा ने एक डेटा तैयार किया जिसमे शारीरिक रूप से अवस्थ और व्यसन के कारण शारीरिक समस्या झेल रहे पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया था जिसमे करीब 300 से ज्यादा पुलिस जवान अनफिट पाए गए ऐसे में अब 50-50के बैच में इन लोगो को सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग देकर फ़ीट किया जा रहा है जिसके सार्थक परिणाम दिखने लगे है। आईजी का कहना है कि ये कोई सजा नही बल्कि पुलिस के जवानो को जीवन जीने की कला सिखाना है ताकि वो अपने परिवार को बेहतर तरीके से चला सके और बेहतर पुलिसकर्मी बनकर बेहतर पुलिसिंग कर सके। ट्रेनिंग के दौरान पुलिस कर्मियों को शारीरिक व्यायाम से लेकर योगा और मेडिटेशन कराया जाता है,इन्हें हफ्ते में एक दिन का अवकाश दिया जाता है खान-पान में भी यहाँ सख्ती बरती जाती है जिसका असर ये पुलिस कर्मी खुद भी महसूस कर रहे है। ट्रेनिंग ले रहे पुलिस कर्मियों का कहना है कि ट्रेनिंग से उनके शारीरिक समस्या का समाधान तो हुआ ही है साथ ही साथ उनका वजन 4 से 5 किलो तक कम हो गया है और वो अब खुद को 4 से 5 साल युवा महसूस कर रहे है।

सुरक्षित बैंकिंग के लिए पुलिस द्वारा सुरक्षा जांच

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 दिसम्बर 2025
(घटती-घटना)।

जिला में सुरक्षित बैंकिंग और आपराधिक गतिविधियों में कमी लाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने 10 दिसंबर 2025 को जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारी को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में शासकीय एवं गैर शासकीय बैंकों की सुरक्षा की जांच करें। इन निर्देशों के तहत,थाना और चौकी प्रभारी ने बैंकों में प्रमुख सुरक्षा बिंदुओं की जांच की, जिसमें सीसीटीवी कैमरों की स्थिति, सुरक्षा गार्ड की संख्या और उनकी मौजूदगी, बैंकों में आपातकालीन सायरन की स्थिति, सुरक्षाकर्मियों के पास हथियार और कारतूसों की संख्या, और कर्मचारियों का सत्यापन शामिल था। इसके अलावा, शाखा प्रबंधकों को यह निर्देश दिया गया कि वे बैंकों में संदिग्ध व्यक्तियों और गतिविधियों के बारे में नजदीकी थाने या पुलिस कंट्रोल रूम में तुरंत सूचना दें। यह सुरक्षा जांच आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बैंकिंग प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

मुंबई में राष्ट्रीय पश्चिम भारत विज्ञान मेले का भव्य शुभारंभ

नेहरू साइंस सेंटर में चमकी चार राज्यों की प्रतिभा,सरगुजा के मॉडल बने मुख्य आकर्षण

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

नेहरू साईस सेंटर मुंबई में आज राष्ट्रीय पश्चिम भारत विज्ञान मेला (2025-26) WISF का भव्य उद्घाटन हुआ,जहाँ विज्ञान और नवाचार की दुनिया में कदम रख रहे चार राज्यों में छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान के शिक्षकों ने भी प्रतिभागी और भाग लिया। प्रतिभागियों ने 20 व्यक्तिगत, टीम प्रोजेक्टस और शिक्षक,शिक्षिकाओं ने 11 शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदर्शन में अपनी अनोखी परियोजनाओं से सबका ध्यान आकर्षित किया। मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर मेले का शुभारंभ किया गया, जिसमें वैज्ञानिकों,शिक्षाविदों,स्कूल प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि 'विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के समग्र विकास की आधारशिला है। ऐसे आयोजन शोध और नवाचार की सोच को मजबूत बनाते हैं। '

सरगुजा के मॉडल बने मुख्य आकर्षण : मेले में सरगुजा जिले से शामिल दो मॉडल विशेष रूप से ध्यान का केंद्र बने 'वॉइस एंड ब्लूटूथ कंट्रोल्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम' को मार्गदर्शक श्रीमती चंदा श्रीवास्तव विद्यालय शास. उ.मा. विद्यालय रामपुर,अंबिकापुर के छात्र ललित राजवाड़े एवं शौर्य महंत ने मिलकर प्रदर्शित किया। यह आधुनिक मॉडल घर की विभिन्न सुविधाओं को वॉइस कमांड और ब्लूटूथ के माध्यम से नियंत्रित करने की तकनीक पर आधारित है, जिसने दर्शकों की खूब सराहना प्राप्त की। व्यक्तिगत मॉडल में 'डाय चेक' को छात्र सुमेश्वर गुप्ता ने शिक्षक श्री प्रत्यूष दुबे सेजेस सरगुजा के मार्गदर्शन में प्रदर्शित किया। दोनों मॉडलों ने सरगुजा जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए मेले में विशेष पहचान बनाई। साथ ही राजस्थान के 'सहस्त्रबाहु' महाराष्ट्र के साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, को खुब सराहना मिली।

विज्ञान प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र

मेले में रोबोटिक्स, अक्षय ऊर्जा,पर्यावरण संरक्षण, कृत्रिम बुद्धिमता और स्वास्थ्य तकनीक से जुड़े कई मॉडल प्रस्तुत किए गए। जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। विज्ञान प्रदर्शनी 10 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। साथ-साथ विभिन्न कार्यशालाएं और वैज्ञानिकों के साथ इंटरेक्टिव सत्र भी आयाजित किये जायेंगे। निश्चित ही इस आयोजन से बच्चों और विजिटर्स को विज्ञान और नवाचार की नई-नई तकनीकों का ज्ञान मिलेगा।

बलरामपुर जिले में बड़ा राजस्व घोटाला...छह गांवों की सरकारी और निजी भूमि एक ही परिवार के नाम पर दर्ज...डीएम के पास पहुंची शिकायत

-संवाददाता-
राजपुर,10 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में बड़ा भूमि घोटाला सामने आया है। यहां कई ग्रामों की शासकीय एवं निजी भूमि को अवैध तरीके से एक ही परिवार के नाम कर दिए जाने का गंभीर आरोप लगा है। इस संबंध कई पंचायत के ग्रामीणों ने कलेक्टर बलरामपुर को लिखित शिकायत देकर तत्काल जांच एवं कार्रवाई की मांग की है।

क्या है शिकायत : ग्रामीणों ने शिकायत की है कि ग्राम पंचायत कोदौरा, कोटडीह, भेण्डरी, परसवार खुर्द, करगडीहा और पकराडी में स्थित कुल लगभग 60 से 70 एकड़ भूमि (शासकीय एवं भू-स्वामियों की निजी भूमि) को कथित रूप से तहसीलदार राजपुर और संबंधित पटवारी की मिलीभगत से एक ही परिवार के सात लोगों के नाम पर नामांतरण की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरा नामांतरण ऑनलाइन दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर किया गया है। महज कुछ समय के भीतर बड़ी मात्रा में भूमि गुप्ता परिवार के नाम चढ़ा दी गई।

गड़बड़ी का इस तरह हुआ खुलासा : ग्रामीणों ने बताया कि धान खरीदी पंजीयन के लिए उन्होंने ऑनलाइन खसरा/बी-1 निकाला, तो वास्तविक भूमि स्वामियों के नाम की जगह गुप्ता परिवार के नाम दर्ज मिले। इस गंभीर विसंगति की सूचना एक सप्ताह पूर्व पटवारी एवं तहसीलदार को दी गई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई।

गुस्साए ग्रामीण पहुंचे डीएम के पास : इसके बाद ग्रामीणों का धैर्य टूट गया और वे सामूहिक रूप से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विस्तृत जानकारी के साथ लिखित शिकायत सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की।

ग्रामीण अंचलों में आवागमन की मिली बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज वर्चुअल माध्यम से जिले के दुर्गम एवं बस-विहीन मार्गों में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत शुरू हुई बस सेवाओं से हजारों ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार तक पहुंच में सुविधा मिलेगी। अम्बिकापुर बस स्टैंड में आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह एवं निगम महापौर श्रीमती मंजूषा भगत ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पार्षद श्रीमती प्रियंका गुप्ता, श्रीमती श्वेता गुप्ता, कलेक्टर श्री विलास भोसकर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री विनय सोनी सहित विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे। महापौर श्रीमती मंजूषा भगत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का सीधा लाभ ग्रामीण जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जहां कभी आवागमन का कोई साधन उपलब्ध नहीं था, वहां अब बस की नियमित पहुंच से लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। महापौर श्रीमती भगत ने मुख्यमंत्री बस योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त किया और कहा कि ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में यह ऐतिहासिक पहल है।

श्री रामलला दर्शन योजना के तहत सरगुजा संभाग के 850 श्रद्धालु तीर्थयात्री अयोध्या के लिए रवाना

जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर स्पेशल ट्रेन को किया रवाना,दर्शानार्थियों को दी शुभकामनाएं...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना के अंतर्गत सरगुजा संभाग के 850 श्रद्धालु तीर्थयात्री आज अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन में तीर्थयात्रियों की विशेष ट्रेन को जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह, महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, जिले के जनप्रतिनिधिगण, टूरिज्म बोर्ड सहायक संचालक सरगुजा श्री आशिष वर्मा तथा रेलवे एवं आई.आर.सी.टी.सी. के अधिकारी कर्मचारीगण अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में उपस्थित रहे। अतिथियों ने सभी यात्रियों को सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं। उप संचालक समाज कल्याण एवं नोडल अधिकारी श्री व्ही. के. उके ने बताया कि जिले के जनपद पंचायत अंबिकापुर से 17, उदयपुर से 19, लखनपुर से 17, लुण्ड्रा 17, बतौली 17, सीतापुर से 18, मैनपाट से 15, नगर निगम अंबिकापुर से 30 नगर पंचायत लखनपुर से 07 तथा नगर पंचायत सीतापुर से 07 कुल 164 तीर्थ यात्री अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए हैं। यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं देखभाल हेतु जिले से अनुरक्षक दल भी उनके साथ भेजा गया है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को भोजन, आवास एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह विशेष ट्रेन यह यात्रा दिनांक 13.12.2025 को वापस अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। सरगुजा संभाग के सभी जिलों से शासन द्वारा निर्धारित यात्री कोटा में सरगुजा से 164, जशपुर से 204, बलरामपुर-रामानुजगंज से 164, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से 57,कोरिया से 108, सुरजपुर से 147 कुल 850 दर्शानार्थी अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए हैं।

धार्मिक आस्था और संवेदना का संगम : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आरंभ की गई 'श्री रामलला दर्शन योजना' का उद्देश्य आमजन, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या धाम के दर्शन का अवसर प्रदान करना है। यह योजना न केवल श्रद्धा और आस्था को सशक्त बनाती है, बल्कि शासन की संवेदनशीलता और जनसेवा के भाव को भी दर्शाती है।

जिला कांग्रेस कमेटी ने अग्रसेन चौक पर किया प्रदर्शन

- केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी,पुलिस से हुई झुमाझटकी
- नेशनल हेराल्ड मामले में मोदी सरकार के तानाशाही रवैये पर हुआ पुतला दहन

-संवाददाता-
सूरजपुर,10 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर मोदी सरकार के द्वारा सोनिया गांधी व राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने के मामले में धमकी की राजनीति और तानाशाही रवैये के मामले में कांग्रेस के प्रदेशव्यापी आह्वान में स्थानीय अग्रसेन चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जमकर नारेबाजी करते हुए पीएम मोदी का पुतला दहन किया गया।

कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि देश में अर्थव्यवस्था की बर्बादी,फैलती नफरत,बेरोजगारी, फेल विदेश नीति के साथ अमेरिका और चीन की धमकी से देश का ध्यान भटकाने के लिए केन्द्र सरकार नेशनल हेराल्ड के मुद्दे को उछाल रही है और कांग्रेस व गांधी परिवार के खिलाफ लगातार तानाशाही मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा राष्ट्र व प्रदेश स्तर पर इसका विरोध सड़क में उतरकर किया जा रहा है। सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त अध्यक्ष शशि सिंह के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय डोसी की अगुवाई में अग्रसेन चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने केन्द्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस को चकमा देकर पुतला दहन किया और पुलिसकर्मियों के साथ कांग्रेसियों की झुमाझटकी भी हुई। इस दौरान जीएस मिश्रा, विमलेश दत्त तिवारी, सुनील अग्रवाल, दीप्ती स्वाई, विनय मिश्रा, बिहारी कुलदीप, प्रवेश गोयल, प्रदीप साहू, नरेन्द्र यादव, विक्की समद्दार, परमेश्वर राजवाड़े, दिलीप सोनी, सकील हुसैन, अजय सोनवानी, देवेश राजवाड़े, इमरान इराकी, पारस राजवाड़े, कौनेन अंसारी, लालचंद देवांगन, संजय सोनी, कुंदन विश्वकर्मा, भोला शर्मा, मो. अजहर, जबारूल खान, गिरधारी साहू, सुनील सारथी, आशीष सिंह, समीर, विनोद सिंह, शांतू डोसी, दीपक साहू, शक्ति ठाकुर, रामनारायण, हेमंत साहू, बालेन्द्र सिंह, जमील सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, किसान कांग्रेस, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस, एनएसयूआई तथा अनुसांगिक संगठनों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे।

सपना चौधरी के वकील ने कोरबा के जश्न रिसॉर्ट को भेजा 50 लाख का नोटिस...

कॉपीराइट एक्ट से जुड़ा है मामला

-संवाददाता-
कोरबा,10 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

ऊर्जा नगरी कोरबा में सपना चौधरी के कार्यक्रम को लेकर जमकर बवाल हुआ था और इस मामले में खुद सपना ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। अब एक नया मामला सामने आया है। इस म्यूजिकल कार्यक्रम को लेकर जश्न रिसॉर्ट, कोरबा के संचालक को फॉनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (पीपीएल) ने 50 लाख रुपये हर्जाने का नोटिस भेजा है। यह नोटिस कॉपीराइट उल्लंघन के आरोपों पर आधारित है।

क्या है नोटिस भेजने की वजह..?

दरअसल किसी भी कॉपीराइटेड संगीत का उपयोग करने के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है और पीपीएल का आरोप है कि 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित 'सपना चौधरी म्यूजिकल इवेंट' से पहले ही रिसॉर्ट को लिखित चेतावनी दी गई थी। 6 अक्टूबर को Apprehension Notice और 10 नवंबर को Final Legal Notice भेजने के बावजूद लाइसेंस नहीं लिया गया। पीपीएल का कहना है कि रिसॉर्ट परिसर में बिना अनुमति संगीत प्रसारित होने दिया गया, जो कॉपीराइट कानून का सीधा उल्लंघन है।

कॉपीराइट उल्लंघन का भागीदार बताया रिजॉर्ट मालिक को

सपना चौधरी के वकील द्वारा यह नोटिस भेजा गया है। जिसमें फर्म पीपीएल का कहना है कि जश्न रिसॉर्ट के पार्टनर और ऑपरेटर होने के नाते संचालक पर कानूनी जिम्मेदारी तय होती है। कॉपीराइट कानून के मुताबिक कोई भी स्थल संचालक जो अपने परिसर को बिना लाइसेंस संगीत प्रदर्शन के लिए उपलब्ध कराता है, वह उल्लंघन का भागीदार माना जाता है। आयोजकों पर जिम्मेदारी डालकर रिसॉर्ट अपनी कानूनी बाध्यता से नहीं बच सकता। पीपीएल ने आगे कहा हैं कि उनकी वेबसाइट पर लाखों साउंड रिकॉर्डिंग्स का अधिकारिक डाटा उपलब्ध है, जिसका लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

50 लाख रुपए का हर्जाना मांगा

पीपीएल ने रिसॉर्ट प्रबंधन से दोबारा मांग की हैं कि पिछले कॉपीराइट उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये हर्जाना और लाइसेंस शुल्क जमा किया जाए। भविष्य में किसी भी कार्यक्रम में पीपीएल के साउंड रिकॉर्डिंग्स का उपयोग बिना लाइसेंस न किया जाए।

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का दिया गया हवाला

री-ज्वाइंडर में बॉम्बे हाई कोर्ट के उन आदेशों का भी हवाला दिया गया है, जिनमें अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिना लाइसेंस किसी भी स्थल पर कॉपीराइट संगीत बजाना अवैध है। संगीत कार्यक्रम की अनुमति देने वाला स्थल संचालक भी उल्लंघन का आरोपी माना जाएगा। पीपीएल ने यह भी चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी कार्यक्रम में बिना लाइसेंस संगीत का उपयोग पाया गया तो तुरंत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

स्टांप पर हस्ताक्षर करने से मना करने पर पति ने कीटनाशक सेवन कर दी जान

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

रायगढ़ के कापू में एक युवक ने कीटनशक सेवन कर आत्महत्या कर ली। वह पत्नी पर चरित्रशंका करता था। इस लिए वह अलग रहने के लिए पत्नी से स्टांप पर हस्ताक्षर करा रहा था। हस्ताक्षर करने से पत्नी मना कर दी तो वह कीटनाशक सेवन कर लिया। इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुरु प्रसाद पिता मस्त राम यादव उम्र 32 वर्ष ग्राम जमदगाह थाना कापू का रहने वाला था। वह बोरबेल में काम करता था। वह पत्नी बेलाशो पर चरित्रशंका करता था। इस लिए वह कुछ दिन पूर्व पत्नी के साथ मारपीट भी किया था। मारपीट किए जाने से पत्नी मायके चली गई थी। इसके बाद वह वापस आ गई थी। 8 दिसंबर को गुरु प्रसाद स्टांप लेकर घर आया और अलग-अलग रहने के लिए पत्नी को हस्ताक्षर कराने लगा। पत्नी स्टांप पर हस्ताक्षर करने से मना कर दी। इससे क्षुब्द होकर पति ने पत्नी के सामने की कीटनाशक सेवन कर लिया। परिजन द्वारा उसे इलाज के लिए कापू अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस विभाग ने की सराहना, 'नशा छोड़ो घर जोड़ो' अभियान को दिया पूरा सहयोग

-संवाददाता-
सूरजपुर,10 दिसम्बर 2025 (घटती-घटना)।

पुलिस के कप्तान एसएसपी प्रसांत ठाकुर ने ए आज़ाद वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्ति जागरूकता अभियान 'नशा छोड़ो घर जोड़ो' की औपचारिक शुरुआत करते हुए पोस्टर का विमोचन किया,पुलिस विभाग ने इस पहल को समाज सुधार की दिशा में एक अत्यंत प्रभावी कदम बताते हुए फाउंडेशन को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया...ए आज़ाद वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया यह अभियान समाज से नशे की बुराइयों को दूर करने और युवाओं, महिलाओं तथा परिवारों को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने पर केंद्रित है...संगठन का उद्देश्य शराब,तंबाकू एवं नशीली दवाइयों के कारण होने वाली सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करना और लोगों को स्वस्थ,सुरक्षित एवं सशक्त जीवन की ओर प्रेरित करना है...अभियान के तहत चिन्हित गांवों में 'नशा मुक्ति चैंपियन' की टीम गठित की जाएगी,जो गांव-गांव जाकर लोगों को नशे से मुक्ति के लिए प्रेरित करेगी...फाउंडेशन ग्राम-स्तर पर सामुदायिक बैठकों, रैलियों और परामर्श सत्रों का आयोजन करेगा,जिसमें विशेषज्ञ,सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे...इन कार्यक्रमों का मकसद है...नशे की आदत से जूझ रहे लोगों को सही मार्गदर्शन देना, उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना और परिवारों को मानसिक एवं सामाजिक सहयोग प्रदान करना... इसके साथ ही,अभियान में सरकारी हेल्पलाइन,नशा मुक्ति केंद्रों तथा उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना भी शामिल है,ताकि जरूरत पड़ने पर लोग तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें। ए आज़ाद वेलफेयर फाउंडेशन घरेलू हिंसा की रोकथाम,नशीले पदार्थों के अवैध उपयोग पर नियंत्रण तथा नशे से होने वाली घटनाओं को कम करने के लिए भी लगातार कार्य करेगा।

अमृत भारत योजना की रफ्तार तेज लेकिन कोयला धूल से बैकुंठपुर स्टेशन बेहाल

6 करोड़ की आधुनिकीकरण परियोजना....पर यात्रियों को कोल डस्ट से नहीं मिली राहत

16 लाख टन कोयला लोडिंग: आधुनिक स्टेशन पर भी यात्रियों का 'कोल क्राइसिस' जारी

बैकुंठपुर स्टेशन का कायाकल्प बनाम कोल साइडिंग की धूल...यात्रियों के बीच टकराहट

अमृत भारत योजना प्रगति पर, लेकिन कोल साइडिंग ने बिगाड़ी स्टेशन की 'क्लीन इमेज'

अमृत भारत स्टेशन योजना: बैकुंठपुर स्टेशन का कायाकल्प तेज... लेकिन कोल साइडिंग की धूल से यात्रियों की परेशानी बरकरार

6 करोड़ की लागत से 2 वर्षों से जारी...

हर साल 16 लाख टन कोयला लोडिंग...प्लेटफार्म तक उड़ता डस्ट,यात्रियों के कपड़े-चेहरे तक हो जाते काले

-राजन पाण्डेय-

कोरिया,10 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बैकुंठपुर रोड स्टेशन को आधुनिक स्वरूप देने हेतु लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से तेजी से निर्माण-सुधार कार्य जारी है। स्टेशन में वेटिंग हॉल, शौचालय, साइनेज, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग,Wi-Fi,वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट जैसे कई उन्नत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, लेकिन इन सभी प्रयासों के बीच एक बड़ी चुनौती आज भी जस की तस है स्टेशन से सटे एसईसीएल कोल साइडिंग से उड़ने वाला कोयला धूल, रोजाना कोल लोडिंग के दौरान उड़ने वाला डस्ट यात्रियों के चेहरे, कपड़ों और सामान पर परत की तरह जम जाता है, जिससे लगातार असुविधा और स्वास्थ्य संबंधी समस्या की आशंका बनी रहती है।

16 लाख टन वार्षिक कोयला लोडिंग...प्लेटफार्म तक पहुंच जाता है डस्ट

बैकुंठपुर रोड स्टेशन के ठीक पीछे एसईसीएल चरचा कॉलरी का प्रमुख कोल साइडिंग स्थित है,यहां से हर साल लगभग 16 लाख टन कोयला रेलवे वैगनों में लोड कर अन्य राज्यों और उद्योगों को भेजा जाता है, लोडिंग के दौरान उड़ने वाला डस्ट सीधे स्टेशन प्लेटफार्म तक पहुंचता है, जिससे यात्रियों की बड़ी संख्या हमेशा प्रभावित होती है,स्टेशन की सतह पर कोल डस्ट की मोटी परत जम जाती है, और आधुनिकीकरण के बावजूद स्वच्छता व आराम जैसी बुनियादी जरूरतें प्रभावित होती दिख रही हैं।

एसईसीएल रोड सेल: हर महीने 5,000 टन कोयला ट्रकों से भेजा जा रहा, इससे डस्ट की समस्या और बढ़ी

एसईसीएल चरचा RO कॉलरी में रेलवे रैक उपलब्धता कम होने के कारण रोडसेल शुरू किया गया है,इसके तहत,स्टेशन परिसर में 100 टन क्षमता का कांटा घर बनाया गया है हर महीने 5,000 टन कोयला ट्रकों से बाहरी राज्यों में भेजा जा रहा है, ट्रक मूवमेंट और स्टॉक एरिया स्टेशन के नजदीक होने से यात्रियों को डस्ट की समस्या और बढ़ रही है।

स्टेशन छोटा, प्लेटफार्म सिंगल, 1,500 से ज्यादा यात्री रोज जोखिम उठाकर चढ़ते

उतरते हैं...वर्तमान में बैकुंठपुर रोड स्टेशन में सिंगल और छोटा प्लेटफॉर्म, कई ट्रेनों की बोगियां प्लेटफार्म से आगे निकल जाती हैं, यात्रियों को जोखिम उठाकर चढ़ना-उतरना पड़ता है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने स्टेशन को अमृत भारत योजना में शामिल कर दिया है, जिसके तहत, विस्तृत मास्टर प्लान, उच्च स्तरीय प्लेटफार्म, एस्केलेटर-लिफ्ट, सूचना प्रणाली, वेटिंग एरिया, पार्किंग और पैदल मार्ग जैसे कार्य तेजी से चल रहे हैं,स्थानीय कला और संस्कृति को शामिल करते हुए स्टेशन को आकर्षक सिटी सेंटर मॉडल का रूप देने की भी योजना है।

कोल साइडिंग नहीं हटेगी,लेकिन डस्ट रोकने व्यवस्था सुधारी जाएगी:अनुराग कुमार सिंह

बिलासपुर मंडल के वरिष्ठ डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने साफ कहा कोल साइडिंग हटाई नहीं जाएगी, लेकिन कोल डस्ट रोकने स्प्रिंकलर और अन्य उपायों को और मजबूत किया जाएगा, इसके लिए एसईसीएल को पत्र लिखकर आवश्यक सुधार करने कहा जाएगा, यह बयान साफ करता है कि स्टेशन आधुनिकीकरण के बीच कोयला धूल की चुनौती अब भी बड़ी राह में खड़ी है, जिसे लेकर यात्रियों में असंतोष बना हुआ है।

मुफ्त Wi-Fi, कियोस्क,रूफ प्लाज़ा,नया बैकुंठपुर स्टेशन होगा आधुनिक सुविधाओं से लैस

अमृत भारत योजना के तहत जिन प्रमुख सुविधाओं को शामिल किया गया है, उनमें शामिल हैं मुफ्त वाई-फाई ने स्टेशन-वन प्रोडक्ट कियोस्क,आधुनिक शौचालय,विस्तृत वेटिंग हॉल,कार्यकारी लाउंज, एस्केलेटर-लिफ्ट,मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट,इंटीग्रेशन,लैंडस्केपिंग,भविष्य में रूफ प्लाजा की संभावना,गिट्टी-रहित पटरियों और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर भी फोकस किया गया है।

बैकुंठपुर स्टेशन—फैक्ट शीट

अमृत भारत योजना लागत: 6 करोड़

प्रगति: 2 वर्षों से कार्य जारी

यात्रियों की स्थिति

रोजाना यात्री: 1500+

सिंगल, छोटा प्लेटफॉर्म:

कई बोगियां प्लेटफॉर्म से बाहर:

चढ़ना-उतरना जोखिम भरा

कोल साइडिंग डेटा

वार्षिक लोडिंग: 16 लाख टन

हर महीने रोड सेल: 5000 टन

100 टन क्षमता का कांटा घर निर्मित

स्टेशन परिसर तक डस्ट का सीधा प्रभाव

योजना में मिलने वाली सुविधाएं

Wi-Fi

वेटिंग हॉल

आधुनिक शौचालय

वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट

एस्केलेटर-लिफ्ट

पार्किंग व सर्कुलेटिंग एरिया

डिजिटल सूचना प्रणाली

स्थानीय कला पर आधारित सजावट

आधुनिक स्टेशन,पुरानी समस्या... कोल साइडिंग का धुआँ,यात्रियों की हवा क्यों ?

अमृत भारत स्टेशन योजना ने पूरे देश में रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प को नई गति दी है। बैकुंठपुर रोड स्टेशन भी इसी नई सोच का हिस्सा है। लगभग 6 करोड़ की लागत से स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है Wi-Fi से लेकर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म तक,लेकिन सवाल यह है कि क्या आधुनिकता केवल स्टेशन बिल्डिंग तक सीमित होगी,या यात्रियों की सांसों तक भी पहुंचेगी? बैकुंठपुर स्टेशन से लगे कोल साइडिंग में हर साल 16 लाख टन कोयला लोड होता है। यह वही स्टेशन है, जहां ट्रेन का इंतजार करते हुए यात्री अपने रूमाल से बार-बार चेहरा पोंछते हैं, क्योंकि कोल डस्ट इतनी प्रचंडता से उड़ता है कि प्लेटफॉर्म से लेकर बैठने की जगह तक हर चीज पर काली परत चढ़ जाती है,एक तरफ करोड़ों का आधुनिकीकरण, दूसरी तरफ कोयले की धूल यह विरोधाभास स्थानीय प्रशासन और रेलवे दोनों के लिए चुनौती है, यदि यात्रा का अनुभव बेहतर बनाना लक्ष्य है,तो कोल डस्ट कंट्रोल को योजना का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना होगा, सीनियर डीसीएम का बयान साइडिंग नहीं हटेगी, लेकिन स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे यह समाधान नहीं, केवल एक अस्थायी उम्मीद है जब तक साइडिंग की कार्यप्रणाली को वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित नहीं किया जाएगा,तब तक यात्रियों को आधुनिक स्टेशन नहीं,आधुनिक धूल ही मिलेगी।

आवश्यकता है

दैनिक समाचार पत्र में कार्य करने हेतु निम्न पदों के लिए योग्य कर्मठ, जुझारू, महिला/पुरूष की आवश्यकता है।

स.क्र.	पद	संख्या	वेतन
01	सह संपादक	1 पद	15,000
02	समाचार संपादक	1 पद	15,000
03	प्रबंध संपादक	1 पद	15,000
04	विज्ञापन प्रभारी	2 पद	10,000 से 15,000
05	ब्यूरो चीफ	1 पद	10,000 से 15,000
06	संवाददाता	2 पद	8000 से 12,000
07	कार्यालय सहायक	1 पद	7000

नोट:- आवेदक फोन पर संपर्क ना करें।
स्वयं बायोडाटा के साथ कार्यालय में संपर्क करें।

पता-कार्यालय दैनिक समाचार पत्र घटती-घटना शनि मंदिर के पास, नमनाकला, अम्बिकापुर छत्तीसगढ़, मो.नं. - 93401 54656, 98265-32611

कार्यालय अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ/स) अम्बिकापुर मण्डल अम्बिकापुर

निविदा आमंत्रण तिथि:- 08.12.2025

ई-प्रोक्यूरमेंट निवदा सूचना

01. निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये Log in करें http://eproc.cgstate.gov.in
02. संबंधित संभाग- स.क्रं. 1 मनेन्द्रगढ़, स.क्रं. 2 से 6 सूरजपुर संभाग
03. स.क्रं. 1 से 6 - द वर्ग एवं ऊपर ठेकेदार
04. ऑनलाईन निविदा डालने की अंतिम तिथि- 30.12.2025

सरल क्र.	एन.आई.टी. क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3	4
1	221	संभाग मनेन्द्रगढ़ के विभिन्न मार्गों में रोड फर्नीचर कार्य । (प्रथम आमंत्रण)	42.37
2	222	लो.नि.वि. उप संभाग प्रेमनगर एवं सूरजपुर अंतर्गत विभिन्न मार्गों में रोड मार्किंग एवं सेफ्टी बोर्ड का कार्य ।(प्रथम आमंत्रण)	40.00
3	223	लोक निर्माण विभाग संभाग सूरजपुर अंतर्गत विभिन्न 07 नग निर्मित मार्गों में आर एस एवं आर एफ का कार्य । (प्रथम आमंत्रण)	59.05
4	224	लोक निर्माण विभाग संभाग सूरजपुर अंतर्गत विभिन्न 17 नग निर्मित मार्गों में आर एस एवं आर एफ का कार्य । (प्रथम आमंत्रण)	53.54
5	225	जिला सूरजपुर के सलका केतका राजापुर परशुरामपुर रामानुजनगर माजा कुड़ेली मार्ग में रोड सेफ्टी एवं रोड फर्नीचर आईटम प्रोवाइड एवं फिक्सिंग कार्य ।	99.99
6	226	जिला सूरजपुर के कमलपुर पोड़ी देवनगर मार्ग रोड सेफ्टी एवं रोड फर्नीचर आईटम प्रोवाइड एवं फिक्सिंग कार्य ।	53.41

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग
अम्बिकापुर मण्डल अम्बिकापुर

जी नंबर-252605329/4

कार्यालय उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जिला-सूरजपुर (छ0ग)

दूरभाष-07775-266265, फैक्स- 266579 ई.मेल-spoffice.surajpur-cg@gov.in

क्रमांक-उमनि/व.पु.अ./सूरज/र.नि./1883/2025 सूरजपुर, दिनांक-06/12/2025

छ.ग. शासन के राज्यपाल की ओर से लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार से प्रपत्र अ में प्रतिशतः दर पर छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा भवन निर्माण कार्य हेतु जारी एसओआर दिनाँक 01.01.2025 के आधार पर इकाई अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिये दर्शित तिथि अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में पजीकृत / स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है-

- निविदा आमंत्रण की सूचना-

01-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 15 दिसम्बर 2025 सायंकाल 05:30 बजे तक।
02-निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि - 19 दिसम्बर 2025 सायंकाल 05:30 बजे तक।
03-निविदा खुलने तिथि - 22 दिसम्बर 2025 प्रातः 11:00 बजे ।

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
01.	थाना सूरजपुर में मालखाना भवन का निर्माण कार्य	06.00 लाख रूपये	5,000/-	750/-	06 माह वर्षा ऋतु सहित

नियम एवं शर्तें:-
01. निविदा प्रपत्र का शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में चालान जमा कर (हेड -0055 पुलिस 800 अन्य प्राप्तियां) चालान की मूल प्रति आवेदन एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय में जमा करने के पश्चात् ही निविदा प्रपत्र प्रदान किया जावेगा ।
02. निविदा से संबंधित आवश्यक नियम व शर्तें तथा अन्य विस्तृत जानकारियां कार्यालयीन अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
03. उमनि एवं वरि. पुलिस अधीक्षक सूरजपुर को अंतिम अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये निविदा निरस्त कर सकते हैं, एवं निविदा की तिथि में संशोधन कर सकते हैं, या पुनः निविदा आमंत्रित कर सकते है ।

उमनि एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जिला-सूरजपुर (छ0ग0)

जी नंबर-252605313/3

बहरासी में रोजगार सहायक पर मनमानी के आरोप से ग्रामीणों में आक्रोश

कलेक्टर से तत्काल कार्रवाई की मांग...पूर्व विधायक गुलाब कमरों से भी मिले ग्रामीण

-राजन पाण्डेय-

एमसीबी/बहरासी,10 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।

ग्राम पंचायत बहरासी में मनरेगा संचालन में अनियमितताओं, फर्जी हाजिरी और मनमानी के आरोपों ने ग्रामीणों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंचों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सामूहिक हस्ताक्षरित आवेदन देकर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से आरोपी रोजगार सहायक आशा सेन पर त्वरित कार्रवाई की मांग की है,ग्रामीणों का आरोप है कि मनरेगा कार्यों की शुरुआत न तो पंचायत प्रतिनिधियों से पूछकर की जाती है और न ही ग्रामवासियों की सहमति ली जाती है। कई सोकता गढ़ा, तालाब निर्माण और अन्य मजदूरी आधारित कार्यों में बिना श्रमिकों की उपस्थिति के फर्जी हाजिरी लगाकर भुगतान किया जा रहा है, जिसे ग्रामीणों ने सरकारी धन का दुरुपयोग और खुली मनमानी बताया है।

शिकायत मिली है...जांच कराएंगे जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम

मामले में जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम ने बताया शिकायत मिली है जांच कराई जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पूर्व विधायक गुलाब कमरों से मिले ग्रामीण समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाया जाएगा

भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र के बहरासी ग्राम से दर्जनों ग्रामीण मनेंद्रगढ़ पहुंचकर पूर्व विधायक गुलाब कमरों से मिले और मामले की विस्तृत जानकारी दी। ग्रामीणों ने क्षेत्र की अन्य समस्याओं को भी उनके सामने रखा, पूर्व विधायक ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि हर शिकायत को प्राथमिकता से लिया जाएगा और प्रशासन के साथ समन्वय कर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा, इधर, ग्रामीणों ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से भी मुलाकात की,जहां अधिकारियों ने तीन दिनों के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

कई पंचायतों में भी फर्जी हाजिरी आम पर कार्रवाई शून्य,ग्रामीणों का आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ बहरासी ही नहीं,क्षेत्र की अन्य पंचायतों में भी फर्जी हाजिरी, मनरेगा में अनियमितताएँ और पारदर्शिता की कमी लंबे समय से बनी हुई है, काम करने वाले मजदूरों को भुगतान पाने के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं जबकि जिन्होंने एक दिन भी काम नहीं किया,उनके खातों में नियमित भुगतान जा रहा है,ग्रामीणों ने कहा कि जांच और कार्रवाई के अभाव ने ऐसे कर्मचारियों के हौसले बढ़ा दिए हैं और प्रशासन को इस स्थिति पर तत्काल संज्ञान लेने की जरूरत है।

सीएम साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन पहुँचे अस्पताल

बैकुंठपुर विधायक भईयालाल राजवाड़े के स्वास्थ्य का लिया जायजा

-संवाददाता-

कोरिया/रायपुर,10 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।

विधायक भईयालाल राजवाड़े के स्वास्थ्य में आई समस्या के चलते मंगलवार को प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना,मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित निजी अस्पताल पहुँचे,जहाँ राजवाड़े उपचाररत हैं। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों को निर्देश दिए कि उपचार में किसी प्रकार की कमी न रहे तथा सभी आवश्यक सुविधाएँ तत्काल उपलब्ध कराई जाए, इस दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहे।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी ली स्वास्थ्य जानकारी

इसी क्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह भी मंगलवार को अस्पताल पहुँचे और विधायक राजवाड़े से मुलाकात की। डॉ. सिंह ने चिकित्सा टीम से उपचार की प्रगति को लेकर चर्चा की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दीं, अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, राजवाड़े पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य जांच और उपचार हेतु भर्ती हैं,और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है।

समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने व्यक्त की चिंता,जताई शुभकामनाएं...

विधायक भईयालाल राजवाड़े के स्वास्थ्य में सुधार की खबर से समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहत व्यक्त की है सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया और व्यक्तिगत रूप से उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है, उल्लेखनीय है कि दो दिन पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत भी अस्पताल पहुंचकर विधायक राजवाड़े की तबीयत का जायजा ले चुके हैं।

बढ़ जलस्तर...बढ़ रकबा...बढ़ी पैदावार...बढ़ी आय

अकलासरई में बना परकोलेशन टैंक किसानों के लिए वरदान

-संवाददाता-

कोरिया,10 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।

जनपद पंचायत सोनहत के अंतर्गत आने वाला अकलासरई गांव वर्षों से पानी की गंभीर कमी का सामना करता रहा है, ऊंचाई पर बसे इस गांव में बारिश का पानी टिक नहीं पाता था और भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा था,परिणामस्वरूप किसान केवल एक ही फसल पर निर्भर रहते,जिससे उनकी आय सीमित और कठिनाइयाँ बढ़ी होती थीं,इसी समस्या का स्थायी समाधान खोजते हुए ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों की सहमति से सोनकुंवर पति जयकरण की भूमि पर परकोलेशन टैंक निर्माण का निर्णय लिया। उद्देश्य था वर्षा जल को संरक्षित करना,मिट्टी में जल रिसाव बढ़ाना, सिंचाई क्षमता मजबूत कर किसानों को दोहरी-तिहरी फसल की ओर बढ़ाना लगभग दो लाख रुपये की स्वीकृत राशि से बना यह टैंक अब पूरे गांव के लिए एक मॉडल जल संरक्षण संरचना बन चुका है।

रोजगार सहायक की पहल...गांव में जागरूकता और तकनीकी समझ बढ़ी

परियोजना को साकार करने में रोजगार सहायक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया कि परकोलेशन टैंक केवल पानी जमा नहीं करता, बल्कि उसे जमीन में धीरे-धीरे रिसने देता है, और आसपास के कुओं, ट्यूबवेल और खेतों में नमी को बढ़ाता है, इस जागरूकता के बाद ग्रामीणों ने भी परियोजना का पूरा सहयोग किया।

परकोलेशन टैंक से बदली सोनकुंवर की किस्मत

पहले सोनकुंवर केवल 1 एकड़ में ही धान की खेती कर पाती थीं, परकोलेशन टैंक बनने के बाद जलस्तर बढ़ा, खेत की नमी बढ़ी, सिंचाई आसान हुई, और इस वर्ष उन्होंने लगभग 2 एकड़ में धान की रोपाई की, अब वे पहली बार बड़े रकबे में रबी फसलें आलू, गोभी, अरहर और सरसों भी ले रही हैं, जिनसे बेहतर उत्पादन और अधिक आमदनी की उम्मीद है।

गांव के अन्य किसानों पर भी पड़ा सकारात्मक असर

सिर्फ सोनकुंवर ही नहीं,अकलासरई के कई अन्य किसानों ने भी बताया कि मिट्टी में नमी बढ़ी है, बोरवेल-कुएँ का जलस्तर सुधरा है,गर्मी में भी खेतों में पानी की उपलब्धता बनी रहती है, परकोलेशन टैंक के कारण गांव में दोहरी फसल लेने की क्षमता बढ़ी है और युवाओं में कृषि विस्तार का उत्साह दिखाई दे रहा है।

अकलासरई जल संरक्षण का नया उदाहरण-

जिस गांव में पानी टिकता नहीं था,अब वही गांव जल संवर्धन, सामुदायिक भागीदारी और टिकाऊ कृषि मॉडल का उदाहरण बन रहा है, परकोलेशन टैंक ने यह साबित किया है कि छोटे निवेश से बड़े बदलाव संभव हैं, बस ज़रूरत है योजनाओं के सही क्रियान्वयन और समुदाय की सहभागिता की।

बालको में 'उत्कृष्ट उत्पादन सम्मान' समारोह का आयोजन,528 कर्मचारी हुए सम्मानित

-संवाददाता-

कोरबा,10 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।

वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में शानदार उत्पादन प्रदर्शन और अनुशासन, उत्पादकता और टीमवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'उत्कृष्ट उत्पादन सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में कुल 528 बालको कर्मचारियों एवं व्यवसायिक साझेदारों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि में विभिन्न यूनिट्स की अहम भूमिका रही। कार्बन यूनिट से 151, पॉटलाइन-1 से 115, पॉटलाइन-2 से 171 तथा रोल्ड प्रोडक्ट्स (आरपी) से 91 कर्मचारियों एवं साझेदारों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान बालको की विभिन्न इकाइयों ने उत्कृष्ट उत्पादन प्रदर्शन कर संगठन की उपलब्धियों में उल्लेखनीय योगदान दिया। पॉटलाइन-1 के 115 कर्मचारियों को उत्पादन लक्ष्य, प्रचालन अनुशासन और समन्वयपूर्ण कार्यशैली में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। नेतृत्व टीम ने उनके सतत प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पॉटलाइन-1 ने प्रदर्शन मानकों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं पॉटलाइन-2 से सर्वाधिक 171 कर्मचारियों को गौरवान्वित किया गया, जो उनकी अनुशासित कार्यप्रणाली, उच्च उत्पादन क्षमता और बेहतर समन्वय का स्पष्ट प्रमाण है। इसके साथ ही कार्बन यूनिट के 151 सदस्यों को उत्पादन, गुणवत्ता और संचालन में निरंतर अनुशासन बनाए रखने के लिए सम्मानित किया गया, जिनके प्रयासों से प्रचालन दक्षता को मजबूती मिली और उत्पादन प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया। इसी तरह रोल्ड प्रोडक्ट्स यूनिट से 91 कर्मचारियों को उत्पादन, गुणवत्ता और प्रचालन दक्षता के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मान से नवाज़ा गया। यह आयोजन बालको की सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और विश्वस्तरीय उत्पादन संस्कृति को दर्शाता है। किसी भी संगठन की असली ताकत कर्मचारी ही होते हैं। उत्कृष्ट उत्पादन उपलब्धियाँ केवल तकनीक का परिणाम नहीं होतीं, बल्कि इसके पीछे कर्मठ कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, समर्पण और टीम भावना होती है। 'उत्कृष्ट उत्पादन सम्मान समारोह' का उद्देश्य ऐसे ही समर्पित प्रयासों को पहचान देना और कर्मचारियों को भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है।

युवाओं को जॉब सीकर नहीं,जॉब प्रोवाइडर बनने का दिया संदेश

स्वदेशी जागरण मंच कोरिया द्वारा उद्यमिता विकास कार्यशाला का आयोजन

-संवाददाता-

कोरिया,10 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)।

स्वदेशी जागरण मंच जिला कोरिया इकाई द्वारा गत दिवस रामानुज शासकीय पी.जी. महाविद्यालय बैकुंठपुर एवं शासकीय कन्या महाविद्यालय बैकुंठपुर में उद्यमिता विकास पर केंद्रित विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं में स्वावलंबन, उद्यमिता और स्वदेशी विचारधारा को प्रोत्साहित करना था। स्वावलंबन जीवन में आमूल परिवर्तन ला सकता है:शंकर त्रिपाठी- कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, छत्तीसगढ़ प्रांत के पूर्णकालिक प्रचारक शंकर त्रिपाठी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा और ज्ञान का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वरोजगार और उद्यम स्थापित करके भी जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि हमें जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, स्वरोजगार, स्थानीय संसाधनों के उपयोग और स्वदेशी मॉडल के जरिए आर्थिक आत्मनिर्भरता को उन्होंने समय की आवश्यकता बताया।

सरकारी योजनाओं का लाभ लें...उद्यमिता की अपार संभावनाएं:शारदा प्रसाद गुप्ता

स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक शारदा प्रसाद गुप्ता ने बताया कि सरकार उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएँ चला रही है,उन्होंने युवाओं को योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि विभिन्न लोन योजनाएँ, कौशल विकास कार्यक्रम,स्टार्टअप और नवाचार प्रोत्साहन योजनाएँ का लाभ लेकर युवा स्वयं का उद्योग शुरू कर सकते हैं, उन्होंने आश्वस्त किया कि मंच की टीम मार्गदर्शन और सहायता के लिए सदैव उपलब्ध रहेगी।

स्वदेशी वस्तुओं का बढ़ता महत्व:हिमांशु अवस्थी

जिला सह-संयोजक हिमांशु अवस्थी ने बदलते वैश्विक परिवेश में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के महत्व को रेखांकित किया, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम हो या आज की वैश्विक टैरिफ वार,स्वदेशी हमेशा एक प्रभावी शस्त्र साबित हुआ है, युवाओं को स्वदेशी उत्पाद अपनाने एवं विदेशी विकल्पों से बचने की अपील की गई।

महाविद्यालय प्राचार्यों ने किया आभार व्यक्त, छात्रों को दी गई स्वदेशी-विदेशी सूची

कार्यक्रम में दोनों महाविद्यालयों के प्राचार्य एम.सी. हिमधर एवं रंजना कच्छप ने स्वदेशी जागरण मंच के इस प्रयास की सराहना की और आभार व्यक्त किया, छात्र-छात्राओं को स्वदेशी एवं विदेशी वस्तुओं की सूची का वितरण भी किया गया, ताकि वे दैनिक जीवन में अधिक जागरूक और आत्मनिर्भर विकल्प चुन सकें।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्रों की उपस्थिति

स्वदेशी जागरण एवं उद्यमिता विकास पर आधारित इस कार्यशाला में दोनों महाविद्यालयों के प्राध्यापकगण तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे, जिन्होंने उत्साहपूर्वक चर्चा में भाग लिया और उद्यमिता से संबंधित प्रश्न भी पूछे।

CMYK

जब रति अग्निहोत्री ने कमल हासन की इंटीमेट लाइफ की उड़ाई थी धज्जियां,भड़क गए थे एक्टर

हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा रति अग्निहोत्री ने 10 दिसंबर को अपना 65 वां जन्मदिन मनाया। उन्होंने कमल हासन के साथ फिल्म एक दूजे के लिए में काम किया,लेकिन उनके बीच अनबन थी। रति ने एक इंटरव्यू में कमल हासन की पर्सनल लाइफ पर टिप्पणी की,जिससे एक्टर तिलमिला उठे थे। रति ने दावा किया था कि उन्होंने कमल हासन के कमरे से आवाजें सुनी थीं...

- रति अग्निहोत्री ने 10 दिसंबर को अपना 65 वां जन्मदिन मनाया...
- एक दूजे के लिए में कमल हासन के साथ किया था काम
- रति ने कमल हासन की पर्सनल लाइफ पर की थी टिप्पणी...

हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अदाकाराओं की जब बात होती है, तो उसमें रति अग्निहोत्री का नाम जरूर शामिल होता है। 80 के दशक में रति अग्निहोत्री ने अपनी वर्सेटैलिटी को काफी बार प्रूफ किया है। महज 16 साल की कम उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने वाली रति अग्निहोत्री ने 10 दिसंबर को अपना 65वां जन्मदिन मना रही हैं।

तमिल-कन्नड़, तेलुगु और हिंदी सहित कई भाषाओं की फिल्मों में काम करने वाली रति अग्निहोत्री ने अपने पूरे करियर में अमिताभ बच्चन से लेकर अनिल कपूर, धर्मेंद्र, काजोल सहित कई सितारों के साथ काम किया। जहां सभी के साथ रति के संबंध अच्छे रहे, तो वहीं कमल हासन एक ऐसे एक्टर थे, जिनसे शुरुआत से ही एक्ट्रेस का 36 का आंके ा था। उन्होंने एक बार तो कमल हासन की इंटीमेट लाइफ को लेकर ऐसा खुलासा किया था, जिससे सुपरस्टार तिलमिला उठे थे।

क्यों रति अग्निहोत्री को पसंद नहीं थे कमल हासन

रति अग्निहोती ने साल 1981 में एक दूजे के लिए से अपनी शुरुआत की थी, जिसमें उनके अपोजिट कमल हासन थे। ये फिल्म उस समय पर एक बड़ी हिट हुई थी। आज के समय में ये बॉलीवुड की मोस्ट रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म बन चुकी है। कमल हासन और रति अग्निहोत्री की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री फिल्म में जहां दर्शकों को पसंद आई, तो वहीं ऑफ कैमरा दोनों एक-दूसरे के सामने खे` भी नहीं होते थे।

दरअसल, कमल हासन एक-दूजे के लिए का तमिल वर्जन कर चुके थे और के बालचंद्र से उनकी दोस्ती काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से वह अक्सर सेट पर फिल्म को लेकर अपना इनपुट देते थे और साथ ही एक्टर्स को इंस्ट्रक्ट भी करते थे। हालांकि,जहां सभी उनकी बात सुनते थे, तो रति को उनके इंस्ट्रक्शन लेना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। जब भी कमल हासन कुछ कहते वह अपोजिट डायरेक्शन में देखने लगती थीं।

कमल हासन के अफेयर की रति अग्निहोत्री ने खोली थी पोल

रति-कमल भले ही एक-दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक प्रोफेशनल तौर पर दोनों ने दोबारा फिल्म देखा प्यार तुम्हारे में काम किया। इस दौरान कथित तौर पर शादीशुदा कमल हासन का नाम एक्ट्रेस सारिका के साथ उे रहा था। जल्द ही सारिका प्रेगेंट हुईं और कमल हासन को मोरल पुलिसिंग फेस करना पे ा।

बॉलीवुड शादी डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक,सारिका संग कमल हासन के अफेयर की खबरों को हवा देते हुए रति अग्निहोत्री ने एक इंटरव्यू में कमल हासन की पर्सनल लाइफ पर भद्दी टिप्पणी की थी। उन्होंने बताया था कि जब वह एक दूजे के लिए शूट कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने कमल के रूम से सेक्स की आवाज सुनी थी और सुबह 4 बजे किसी महिला को उनके रूम से निकलते हुए देखा था। रति ने ये दावा कि शुभा खोटे और माधवी फिल्म का हिस्सा थीं, लेकिन शुभा खोटे पहले से ही शादीशुदा थीं और उनके बच्चे थे और वह खुद कमल हासन से नफरत करती हैं। ऐसे में उनके इंटरव्यू के बाद सभी उंगलियां माधवी पर उठीं।

रति के इल्जामों का कमल हासन ने दिया था मुंहतोड़ जवाब

जब रति अग्निहोत्री का इंटरव्यू पब्लिश हुआ, तो कमल हासन के चरित्र पर कई उंगलियां उठी और उन्हें वुमनाइजर का टैग दे दिया गया। सिने ब्लिट्ज को दिए इंटरव्यू में कमल हासन ने रति अग्निहोत्री को झूठा बताया था और अपना गुस्सा व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था, अगर रति ऐसा कह रही है कि उसने आवाजें सुनी है, तो वह जरूर मेरे बेडरूम में होगी, क्योंकि उस समय मैं सिर्फ अपनी पत्नी वाणी के साथ सेक्स करता था।

इस वॉर के बाद रति अग्निहोत्री और कमल हासन ने एक-दूसरे के साथ कभी भी काम नहीं किया। उनकी आखिरी फिल्म साथ में देखा प्यार तुम्हारा है।

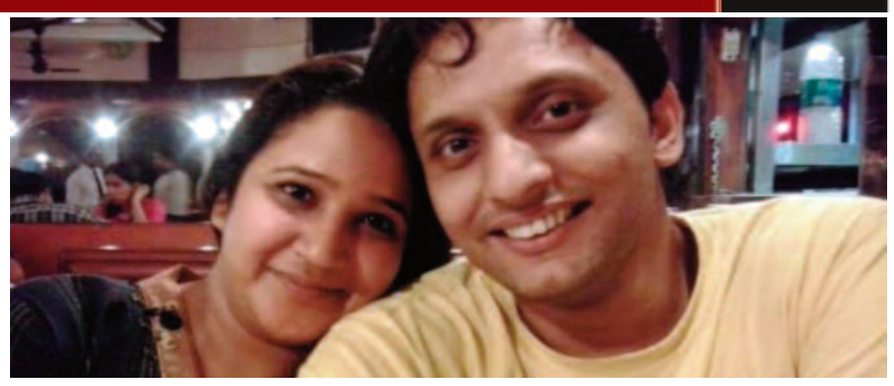

मुस्लिम दूल्हा,हिंदू दुल्हन... परिवार नहीं माना तो भाग गए गोवा

अभिनेता मोहम्मद जीशान अय्यूब ने हाल ही में अपनी इंटरफेथ मैरिज (मुस्लिम-हिंदू) के बारे में खुलासा किया। उन्होंने 2007 में रसिका अगाशे से शादी की थी। शुरुआत में दोनों परिवारों ने इस रिश्ते का विरोध किया था, जिसके कारण शादी के तुरंत बाद वे चार दिनों के लिए गोवा भाग गए थे।

मोहम्मद जीशान अय्यूब ने 2007 में रसिका अगाशे से शादी की। यह जोड़ा,अपने निजी जीवन को सार्वजनिक नजरों से दूर रखना पसंद करता है। हालांकि हाल ही में एक्टर ने अपने विवाह के समय अलग-अलग धर्मों के कारण आने वाली चुनौतियों का खुलासा किया। जीशान अय्यूब मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं जबकि रसिका हिंदू हैं।

शादी के खिलाफ था परिवार

अपनी इस इंटरफेथ मैरिज के बारे में बात करते हुए तनु वेड्स मनु 2 एक्टर ने बताया कि दोनों ही परिवार इसके खिलाफ थे। इस वजह से शादी के तुरंत बाद दोनों 4 दिनों को लिए गोवा भाग गए। शिरोज टीवी से बातचीत में जीशान ने कहा, इस शादी की अपनी कुछ दिक्कते थीं ये हिंदू -मुस्लिम विवाह था। इसलिए सबसे बचने के लिए हम चार दिनों के लिए गोवा भाग गए और किसी से बात न करने का फैसला किया। हमने गोवा में चार दिनों तक खूब मौज की।

साल 2007 में की थी शादी

हालांकि गोवा से लौटने के बाद एक चौंकाने वाली घटना घटी। दोनों के परिवारों ने उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। जीशान ने बताया,हम सितंबर में वापस आए और उसके तुरंत बाद शादी कर ली। शुक्र है, दोनों परिवारों के माता-पिता शादी में शामिल हुए। पहले कुछ महीने असमंजस में बीते क्योंकि हमारे परिवार अलग-अलग धर्मों को मानते थे। कपल ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत साल 2007 में शादी की थी। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम राहा खान है।

कैसे हुई थी प्यार की शुरुआत?

जीशान और रसिका की मुलाकात एनएसडी में हुई थी। रसिका जीशान की सीनियर थीं। इस पर बात करते हुए जीशान ने कहा, रसिका ने पहली बार में ही परीक्षा क्लियर कर ली थी जबकि मैं दूसरी बार में इसे निकाल पाया। दोनों एक दूसरे के अलग-अलग व्यवहार से काफी आकर्षित हुए। वहीं मुंबई में भी पहली मुलाकात भी बहुत अजीब थी क्योंकि एक्टर एक घंटा देर से पहुंचे थे।

सगे भाई की बनीं प्रेमिका,सड़कों पर हुआ विद्रोह,गरीबी ने बदली जिंदगी...ऐसे हुआ उस हीरोइन का अंत

आज हम आपको एक ऐसी हीरोइन की कहानी बताएंगे, जिसने पर्दे पर अपने सगे भाईयों से रोमांस किया और फिर बाद में इसको लेकर जमकर विवाद भी हुआ। हिंदी सिनेमा में आज के दौर में भले ही सबकुछ इतना एडवांस हो लेकिन एक वक्त ऐसा था जब हिंदी सिनेमा की अभिनेत्रियों के लिए कुछ भी करना मानो बड़ी मुश्किल के बराबर होता था। पहले हॉटनेस भी छुप-छुपकर दिखाई जाती थी। यहां तक कि इसी के चलते कई बार विवाद तक हुआ। आज हम आपको एक ऐसी हीरोइन की कहानी बताएंगे, जिसने पर्दे पर अपने सगे भाईयों से रोमांस किया और फिर बाद में इसको लेकर जमकर विवाद भी हुआ।

40 के दशक में मशहूर हुई एक्ट्रेस

हिंदी सिनेमा के नए-नए कदम आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच 40 के दशक में एक एक्ट्रेस आई, जिनका नाम था मीनू मुमताज। इस अदाकारा ने उस जमाने में कुछ ऐसा किया जिसके चर्चे खूब हुए। मुमताज अली की बेटी मीनू मुमताज थीं। मुमताज अली भी अभिनेता ही थे। ऐसे में मीनू के लिए सिनेमा की राह थोड़ी आसान थी। मीनू के भाई मशहूर कॉमेडियन महमूद थे। मीनू का जन्म साल 1942 में मुंबई में हुआ था।

मुंबई में जन्मी और पली-बढ़ी मीनू मुमताज ने अपने पिता से डांस सीखा। डांस की चाह धीरे-धीरे मीनू के कदमों को सिनेमा की दुनिया में ले आई। 4 भाई और 4 बहनों के परिवार में जब मीनू के पिता शराब की लत में डूबे तो जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। हालांकि मीनू की मां नहीं चाहती थीं कि वो एक्ट्रेस बनें। पहले मीनू ने नाटकों में काम करना शुरू किया फिर एक दिन फिल्ममेकर नानूभाई वकील की उन पर नजर पड़ी और यहीं से मिली उन्हें अपनी पहली फिल्म।

फिल्मों में चला मीनू मुमताज का सिक्का

साल 1955 में मीनू मुमताज की पहली फिल्म आई, जिसका नाम था सखी हातिम। महज 13 की मीनू ने इस फिल्म से सिनेमा की दुनिया में कदम रख लिया। साल 1956 में आई फिल्म सीआईडी में उनके नाम को पसंद किया गया। इसके बाद वो हावड़ा ब्रिज, चौदहवीं का चांद, कागज के फूल, साहेब बीवी और गुलाम, यहूदी, ताजमहल समेत कई फिल्मों में नजर आई।

फिल्म नया दौर में उनका गाना रेशमी सलवार कुर्ता जाली का खूब पॉपुलर हुआ। मीनू मुमताज का असली नाम मलिकुन्निसा अली था, लेकिन जब उनकी फिल्में हिट हुई तो उन्होंने नाम बदल दिया। वो ज्यादातर फिल्मों में चैरेक्टर रोल्स और डांस करती नजर आई।

भाई के साथ पर्दे पर किया रोमांस तो हुआ विवाद

साल 1958 में फिल्म आई हावड़ा ब्रिज। इस फिल्म में मीनू के साथ उनके भाई महमूद नजर आए। फिल्म में मीनू ने भाई महमूद के साथ पर्दे पर रोमांस किया। फिल्म में मुमताज और महमूद एक दूसरे के अपोजिट नजर आए थे। ऐसे में फिल्म और स्क्रिप्ट की डिमांड के चलते दोनों को स्क्रीन पर रोमांस भी करना था। फिल्म के गाने गोरा रंग चुनरिया काली में दोनों का रोमांस नजर आया।

हालांकि एक्टर्स होने के नाते दोनों स्क्रीन पर साथ नजर आए और रोमांस भी किया, लेकिन नहीं पता था कि विवाद इतना बढ़ जाएगा। जब फिल्म आई और लोगों ने फिल्म के गानों और फिल्म को देखा तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उस वक्त फिल्म को बैन तक करने की मांग की गई, क्योंकि लोगों का कहना था कि भाई-बहन के रिश्ते को खराब किया जा रहा है। हालांकि फिल्म हिट रही और धीरे-धीरे ये विवाद भी थम सा गया।

शादी के बाद छोड़ा देश और फिर निधन

मीनू मुमताज ने 1963 में फिल्ममेकर एस अली अकबर से शादी कर ली। शादी के बाद मीनू के 4 बच्चे हुए। इसके बाद वो घर-परिवार छोड़कर कुवैत में रहने लगीं और फिर टोरंटो में जाकर बस गईं। हालांकि बीच-बीच में वो कई बार भारत आती जाती रहीं। साल 2003 में मीनू मुमताज की याददाश्त चली गई। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया तो पता चला कि उन्हें ब्रेन में एक ट्यूमर है। इसके बाद उनके ट्यूमर का इलाज हुआ और ठीक हुईं। हालांकि साल 2021 में कैंसर के चलते उनका निधन हो गया।

खेल-समाचार

चौहान,बरुआ,मीर ने बड़े उलटफेर किए

कटक,10 दिसम्बर 2025। ओडिशा मास्टर्स 2025 के मेन ड्रॉ के पहले दिन भारत की युवा टीम ने रौनक चौहान, इशारानी बरुआ और तस्नीम मीर के शानदार प्रदर्शन और बड़े उलटफेर के साथ धूम मचा दी। टॉप परफॉर्मर उन्नति हुड्डा,तन्वी शर्मा और किरण जॉर्ज भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अगले राउंड में पहुंच गईं। भारत की ऐतिहासिक वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा चौहान ने सैयद मोदी इंटरनेशनल टाइटल जीतने वाले जेसन गुनावान को 64 मिनट तक चले रोमांचक ऋ2 मुकाबले में हराकर दिन का सबसे बड़ा नतीजा हासिल किया।

पहला गेम 15-21 से हारने के बाद, भारतीय युवा खिलाड़ी ने शानदार वापसी करते हुए हांगकांग-चीन के तीसरे सीड खिलाड़ी को 21-17, 21-19 से हराया। अब चौहान का सामना साथी भारतीय वरुण कपूर से होगा, जिन्होंने-श्व के भरत लतीश को 56 मिनट में 21-16, 16-21, 21-19 से हराया। टॉप सीडेड मेन्स सिंगल्स प्लेयर्स, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज को ऋ64 में बाई मिला। थारुन ने सिर्फ़ 27 मिनट में मानव चौधरी को 21-5, 21-8 से हराकर प्री-क्वार्टर में जगह बनाई और अब उनका मुकाबला हमवतन गोविंद कृष्णा से होगा, जिन्होंने कविन थंगम को 21-12, 19-21, 21-15 से हराया। दूसरी सीडेड किरण जॉर्ज भी राजेश श्रीकर को 21-12, 21-13 से हराकर आगे बढ़ीं और अगले राउंड में उनका मुकाबला इंडोनेशिया की डेंडी त्रियानस्याह से होगा।

देशर्ट वाईपर्स की रोमांचक एक-रन जीत

टीएलटी 20 में चौथी लगातार विजय

अबूधाबी,10 दिसम्बर 2025। जायद क्रिकेट स्टेडियम में डेजर्ट वाइपर्स ने एमआई एमिरेट्स को एक रन से हरा दिया। यह जीत, जो आखिरी गेंद तक चली, डीपी वर्ल्ड टीएलटी 20 सीज़न चार में वाइपर्स की लगातार चौथी जीत थी। वाइपर्स ने आठ अंकों के साथ टेबल में टॉप पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। 159 रन का बचाव करते हुए, वाइपर्स को शुरू में विकेट लेने में मुश्किल हुई। खेल 19 वें ओवर में पलटा, जब डेविड पायने - जिन्होंने 29 रन देकर चार विकेट लिए - ने तीन अहम विकेट लिए। एमआई के खुजैमा तनवीर ने भी 34 रन देकर दो विकेट लेकर प्रभावित किया, जिससे वाइपर्स ने एक बार फिर अपना संयम दिखाया। दूसरी पारी में, एमआई

एमिरेट्स ने जल्दी एक विकेट खो दिया जब तनवीर ने दूसरे ओवर में जॉनी बेयरस्टो (7 गेंदों में 8 रन) को आउट कर दिया। यह मुहम्मद वसीम (21 गेंदों में 24 रन) और टॉम बैंटन (29 गेंदों में 34 रन) थे जिन्होंने पावरप्ले में एमआई एमिरेट्स को 49/1 के स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने 31 गेंदों में 42 रन की साझेदारी की, इससे पहले कि तनवीर ने रात के अपने दूसरे स्पेल में फिर से वसीम को आउट कर दिया। जब निकोलस पूरन (29 गेंदों में 31 रन) उनके साथ बीच में आए तो बैंटन पूरी तरह से नियंत्रण में दिख रहे थे।

भारत ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को हराकर जीता पदक

भारतीय जूनियर मेंस हॉकी टीम ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर पहली बार जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता। 0-2 से पिछड़ने के बाद,टीम ने आखिरी क्वार्टर में शानदार वापसी करते हुए चार गोल दागे और इतिहास रचा...

चेन्नई,10 दिसम्बर 2025। भारतीय जूनियर मेंस हॉकी टीम ने एक अविश्वसनीय वापसी करते हुए इतिहास रच दिया है। तमिलनाडु के दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में भारत ने कांस्य पदक के मुकाबले में अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर पहली बार जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता। हाफ टाइम तक 0-1 से और तीसरे क्वार्टर के अंत तक 0-2 से पीछे चल रही भारतीय टीम ने आखिरी 15 मिनट में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और शानदार प्रदर्शन किया।

आखिरी क्वार्टर का जोरदार पलटवार

तीसरे क्वार्टर के अंत में सैंटियागो फर्नांडीज के गोल से अर्जेंटीना ने अपनी बढ़त दोगुनी कर दी थी, जिससे भारत पर भारी दबाव आ गया। लेकिन चौथे क्वार्टर में मैच का रुख पूरी तरह से बदल गया। 11 मिनट बाकी रहते अंकित पाल ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागकर स्कोर 1-2 किया और मैच में जान फूंकी। कुछ ही देर बाद, भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला और मनमीत सिंह ने शानदार डिफ्लेक्शन से नौ मिनट शेष रहते स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया।

मैच का रुख पूरी तरह से बदल गया था। भारत की मेहनत रंग लाई जब उन्हें एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला और शारदा नंद तिवारी ने तीन मिनट शेष रहते हुए इसे बाएं कोने में मारकर भारत को 3-2 से आगे कर दिया। आखिरी क्षणों में जब अर्जेंटीना के खिलाड़ी गोलकीपर को हटाकर खेल रहे थे, भारत ने एक और मौका भुनाया। इक्का सिंह ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर 4-2 से शानदार वापसी जीत सुनिश्चित की।

पहली बार जीता पदक

फाइनल सीटी बजते ही भारतीय हॉकी के लिए एक अविस्मरणीय रात की पुष्टि हो गई। आखिरी क्वार्टर में चार गोल करके भारतीय टीम ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में देश को पहला कांस्य पदक दिलाया और घरेलू फैंस को खुशी से सराबोर कर दिया। अब स्पेन और जर्मनी के बीच फाइनल रात 8 बजे आईएसटी से शुरू होगा।

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जापानी टीम घोषित

काजुमा काटो-स्टैफोर्ड संभालेंगे कमान

टोक्यो,10 दिसम्बर 2025। काजुमा काटो-स्टैफोर्ड को मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जापान का कप्तान नियुक्त किया गया है। इस टूर्नामेंट के लिए निखिल पोल और टिमोथी मूर को भी टीम में शामिल किया गया है। यह विश्व कप 15 जनवरी से 6 फरवरी के बीच नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। जापान को ग्रुप सी में रखा गया है, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और आयरलैंड की टीमें भी शामिल हैं। टीम 5 जनवरी को साउथ अफ्रीका के लिए रवाना होगी, जहां 10 जनवरी को तंजानिया और 12 जनवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ वार्मअप अप मैच खेलेगी।

रियो सकुरानो-थॉमस को जापान की अंडर-19 टीम का हेड कोच बनाया गया है, जो इस वक्त जापान की सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम के एक्टिव खिलाड़ी हैं। वहीं, जापान की सीनियर पुरुष टीम के कप्तान केंडल कडोवाकी-फ्लेमिंग अंडर-19 टीम के असिस्टेंट कोच होंगे। निखिल पोल और टिमोथी मूर एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रीमियर कप में जापान के लिए नहीं खेल सके थे। उस टूर्नामेंट में जापान ने मालदीव और कतर को शिकस्त दी थी, लेकिन ओमान के खिलाफ मैच गंवाने के बाद यह टीम सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी।

वहीं, एशियन क्रिकेट काउंसिल प्रीमियर कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले निहार परमार और काइसेई कोबायाशी-डोगेट को इस टीम में शामिल किया गया है। निहार परमार ने मालदीव के खिलाफ 132 गेंदों में 156 रन बनाए थे, जबकि काइसेई कोबायाशी-डोगेट ने कतर के विरुद्ध 73 गेंदों पर 106 रन की पारी खेली थी। पुरुषों के अंडर-19 वर्ल्ड कप के 16वें एडिशन में 16 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं। इन टीमों को चार-चार के चार ग्रुप में बांटा गया है।

मैड्रिड ने चैंपियंस लीग मैच के लिए टीम घोषित की

मैड्रिड,10 दिसम्बर 2025। रियल मैड्रिड ने बुधवार को चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ होने वाले मैच के लिए अपनी टीम में किलियन म्बाप्पे को शामिल किया है,हालांकि उनकी फिटनेस को लेकर संदेह बना हुआ है। फ्रांसीसी सुपरस्टार मंगलवार को ट्रेनिंग में शामिल नहीं हुए थे, और मैड्रिड ने एएफ्पी को बताया कि ऐसा उंगली में फ्रैक्चर और कुछ दूसरी दिक्कतों की वजह से हुआ था। स्पेनिश मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि अगर रियल मैड्रिड पेप गार्डियोला की टीम से हार जाती है, तो मैड्रिड के कोच ज़ाबी अलोंसो को बर्खास्त किया जा सकता है। लॉस ब्लैंकोस ने सभी प्रतियोगिताओं में अपने पिछले सात मैचों में से सिर्फ दो जीते हैं। म्बाप्पे इस सीज़न में टीम के टॉप स्कोरर हैं, जिन्होंने सभी प्रतियोगिताओं में 21 मैचों में 25 गोल किए हैं

सीएम साय की अध्यक्षता में सिविल लाईन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में हुए कई निर्णय

सरेंडर नक्सलियों का केस वापस लेगी छत्तीसगढ़ सरकार

जिला स्तर पर बनेगी कमेटी,14 कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव,025-26 सप्लीमेंट्री एस्टीमेट होगा पेश

रायपुर,10 दिसम्बर 2025। छत्तीसगढ़ सरकार सरेंडर नक्सलियों का केस वापस लेगी। साय कैबिनेट की मीटिंग में बुधवार को मंजूरी मिली है। इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी और जिला स्तरीय कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। अच्छे व्यवहार और नक्सल हिंसा छोड़ने वाले लोगों को राहत दी जाएगी। इसके साथ ही कानूनों को और सरल बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक-2025 के दूसरे संस्करण को भी मंजूरी मिली। इसके तहत 11 विभागों के 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों में बदलाव करके छोटे उल्लंघनों पर प्रशासनिक सजा और तेज निपटारे की व्यवस्था की जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए इसे सरलीकरण किया जाएगा। साथ ही प्रथम अनुपूरक अनुमान 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक को भी स्वीकृति दी गई।छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां जन विश्वास विधेयक का द्वितीय संस्करण लाया जा रहा है।

कैबिनेट बैठक में लिए गए ये अहम निर्णय

1. मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण/वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया है। मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए, जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन को स्वीकृति दी है। यह समिति परीक्षण उपरांत प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्म समर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण तथा नक्सलवाद उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति आत्मसमर्पित नक्सली के अपराधिक प्रकरणों की वापसी के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करेगी। पुलिस मुख्यालय अभिमत सहित प्रस्ताव भेजेगा। शासन द्वारा विधि विभाग का अभिमत प्राप्त कर मामलों को मंत्रिपरिषद उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उपसमिति द्वारा अनुशंसित प्रकरणों को अंतिम अनुमोदन हेतु मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाएगा। केंद्रीय अधिनियम अथवा केंद्र सरकार से संबंधित प्रकरणों के लिए भारत सरकार से आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी। अन्य प्रकरणों को न्यायालय में लोक अभियोजन अधिकारी के माध्यम से वापसी की प्रक्रिया हेतु जिला दण्डाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।
2. मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के विभिन्न कानूनों को समयानुकूल और नागरिकों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से 14 अधिनियमों में संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। उल्लेखनीय है कि कई अधिनियमों में उल्लंघन पर जुर्माना या कारावास के प्रावधान होने से न्यायिक प्रक्रिया लंबी हो जाती है, जिससे आम नागरिक और व्यवसाय दोनों अनावश्यक रूप से प्रभावित होते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के लिए इन प्रावधानों का सरलीकरण आवश्यक है। इससे पहले, राज्य सरकार द्वारा 8 अधिनियमों के 163 प्रावधानों में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2025 अधिसूचित किया गया है। अब 11 विभागों के 14 अधिनियमों के 116 प्रावधानों को भी सरल और अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह विधेयक लाया जाएगा। इस विधेयक में छोटे उल्लंघनों के लिए प्रशासकीय शास्ति का प्रावधान रखा गया है, जिससे मामलों का त्वरित निपटारा होगा, न्यायालयों का बोझ कम होगा और नागरिकों को तेजी से राहत मिल सकेगी। साथ ही, कई अधिनियमों में दंड राशि लंबे समय से अपरिवर्तित होने के कारण प्रभावी कार्यवाही बाधित होती थी, इस विधेयक से वह कमी भी दूर होगी। इन संशोधनों से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां जन विश्वास विधेयक का द्वितीय संस्करण लाया जा रहा है।
3. मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2025-2026 का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2025 का अनुमोदन किया गया।

कैसे काम करेगी जिला-स्तरीय समिति

सरेंडर करने वाले नक्सलियों के खिलाफ केस वापस लेने की प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक जिला-स्तरीय समिति बनाई जाएगी। यह समिति सरेंडर करने वाले नक्सली के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेने के संबंध में पुलिस मुख्यालय को एक रिपोर्ट सौंपेगी। पुलिस मुख्यालय अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव आगे बढ़ाएगा। कानून विभाग की राय लेने के बाद, सरकार मामलों को कैबिनेट उप-समिति के सामने पेश करेगी। उप-समिति के सुझाए गए मामलों को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। केंद्रीय कानूनों या केंद्र सरकार से संबंधित मामलों के लिए भारत सरकार से जरूरी अनुमति ली जाएगी। अन्य मामलों को अदालत में सरकारी वकील के जरिए केस वापस लेने की कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा।

छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर एक्टिव 15 नक्सलियों का सरेंडर

गढ़चिरौली में 11,कांकेर में 4 ने डाले हथियार,सभी पर 1.5 करोड़ का इनाम था

कांकेर,10 दिसम्बर 2025। छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर एक्टिव 15 नक्सलियों ने बुधवार को कांकेर और गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन नक्सलियों पर केंद्र और राज्य सरकारों ने कुल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित किया था। इनमें कुख्यात नक्सली विनोद शयाना भी शामिल है। इसमें से 11 नक्सलियों ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण किया। इन पर कुल 82 लाख रुपए का इनाम था। वहीं, 2 महिला समेत 4 नक्सलियों कांकेर में सरेंडर किया। इन पर 23 लाख रुपए का इनाम घोषित था।

गढ़चिरौली में 4 नक्सलियों ने वर्दी और हथियार भी सौंपे

गढ़चिरौली जिले में 11 सीनियर और हार्डकोर नक्सलियों ने महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के सामने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वालों में 2 DVCM, 3 PPCM, 2 ACM और 4 सदस्य रैंक के माओवादी शामिल हैं। इन सभी पर राज्य और केंद्र सरकार की ओर से कुल 82 लाख रुपए का इनाम था। इनमें से 4 नक्सलियों ने अपनी वर्दी और हथियार भी पुलिस को सौंप दिए। ये सभी नक्सली छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर सक्रिय थे।

DVCM रमेश उर्फ भीमा ने भी डाले हथियार

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में सबसे बड़ा नाम 57 साल के रमेश उर्फ भीमा उर्फ बाजू गुड्डी लेकामी का है,जो भामरागढ़ एरिया का डिवीजनल कमेटी सदस्य था। अन्य सरेंडर करने वाले नक्सली छत्तीसगढ़ के सुकमा, बीजापुर, कांकेर और नारायणपुर जिलों के हैं। सरेंडर नक्सलियों में रमेश के अलावा भीमा उर्फ सीटू उर्फ किरण हिडमा कोवासी , पोरीये उर्फ लकी अदामा गोटा , रतन उर्फ सन्ना मासु ओयाम, कमला उर्फ रागो इरिया वेलाडी, पोरीये उर्फ कुमारी भीमा वेलाडी, रामजी उर्फ मुरा लच्छु पुंगाटी, सोनू पोडियाम उर्फ अजय, प्रकाश उर्फ पांडू पुंगाटी, सीता उर्फ जैनी टोंडे पालो और साईनाथ शंकर माडे शामिल हैं।

पीरियड्स की बीमारी छिपाकर शादी,अब हो गया तलाक

बिलासपुर,10 दिसम्बर 2025। हाईकोर्ट ने तलाक को लेकर फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ पत्नी की अपील खारिज कर दी है। पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी ने पीरियड्स नहीं आने की बीमारी छिपाकर शादी की थी,यह उसके साथ मानसिक क्रूरता है। इसके अलावा वे लंबे समय से अलग रहे हैं। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डिवीजन बेंच ने कहा कि दंपती के बीच रिश्ता सुधरना संभव नहीं। पति ने बताया कि एक दिन पत्नी ने उसकी माहवारी रुकने की जानकारी दी। वह उसे डॉक्टर के पास लेकर गया,डॉक्टर को पत्नी ने बताया कि वह पिछले 10 साल से पीरियड्स नहीं होने की समस्या से जूझ रही है। इसके बाद दूसरे डॉक्टरों से जांच में भी गर्भधारण में गंभीर समस्या सामने आई। पति का कहना था कि पत्नी और उसके परिवार ने यह जानकारी शादी से पहले जानबूझकर छिपाई। इस संबंध में पूछने पर पत्नी ने कहा कि अगर पहले बता देती तो आप शादी से मना कर देते,इसलिए अब मुझे स्वीकार करना होगा। दरअसल, कबीरधाम में रहने वाले दंपती की शादी 5 जून 2015 को हिंदू रीति से हुई थी. दो महीने तक उनके बीच सबकुछ सामान्य रहा,इसके बाद विवाद शुरू हो गए। पति ने फैमिली कोर्ट में दिए गए आवेदन

में दावा किया था कि शुरुआती दो महीनों तक पत्नी का व्यवहार सामान्य रहा,लेकिन बाद में उसने घर के बुजुर्ग माता-पिता,भतीजे-भतीजियों की जिम्मेदारी उठाने पर आपत्ति जताना शुरू कर दिया। इधर पत्नी का आरोप था कि शादी के बाद घर की नौकरानी को काम से हटा दिया गया और सभी घरेलू काम उससे कराए गए। दावा किया कि उसे 'बांझ' कहकर प्रताड़ित किया जाता था। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों ने माना,कि वे वर्ष 2016 से अलग रह रहे हैं। मेडिकल दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट हुआ कि पत्नी का इलाज चल रहा था, पर वह यह साबित नहीं कर पाई कि उसकी स्थिति पूरी तरह ठीक हो गई है। कोर्ट ने पाया कि पति-पत्नी के बीच विवाद इतने गहरे हो चुके हैं कि वैवाहिक संबंध का सामान्य स्थिति में लौटना संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का दूसरा चरण शुरू,180 नए गांव जुड़े बस सुविधा से

रायपुर,10 दिसम्बर 2025। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा अंचल के सुदूर वनांचलों में ग्रामीण परिवहन को नई दिशा देने वाली मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने आज एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से योजना के द्वितीय चरण का औपचारिक शुभारंभ किया तथा वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। दूसरे चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के 10 जिलों के 23 मार्गों पर 24 नई बसों का संचालन प्रारंभ हुआ है, जिससे 180 गांव सीधे बस सुविधा से जुड़ गए हैं। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में शामिल अनेक ग्रामीण उसी बस में सवार होकर पहुंचे, जिसे योजना के प्रथम चरण में प्रारंभ किया गया था। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से आत्मीय चर्चा करते हुए बताया कि अब दूरस्थ इलाकों से ब्लॉक मुख्यालयों तक पहुंचना पहले की तुलना में काफी सहज और सुगम हो गया है। सुकमा-दोरनापाल-कोंटा मार्ग से पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि वे लगभग 110 किलोमीटर की यात्रा बस से कर कार्यक्रम तक पहुंचे, जबकि पूर्व में यह यात्रा बेहद कठिन और समयसाध्य थी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि छत्तीसगढ़ का कोई भी गांव विकास की मुख्यधारा से अलग न रहे।

स्कूल में सांप-बिच्छू पर नजर रखने बच्चो को बचाने, टीचरों को मिले निर्देश

रायपुर,10 दिसम्बर 2025। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने नया निर्देश जारी किया है। अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी करने के साथ ही सांप-बिच्छू पर भी ध्यान रखने को कहा गया है। टीचर्स को जहरीले जीव-जंतुओं को स्कूल परिसर में आने से रोकना होगा। यह आदेश प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को दिया गया है। डीपीआई ने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। वहीं आदेश को लेकर प्राचार्य और हेडमास्टर में नाराजगी है। उन्होंने इस आदेश को बेतुका बताया है। टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि सांप-बिच्छू और जहरीले जीव-जंतु से टीचर को भी खतरा हो सकता है। ऐसे जहरीले जंतुओं से शिक्षकों को कौन बचाएगा। शिक्षकों की नई जिम्मेदारियों की बात करें तो अब स्कूल परिसर में खेलते हुए बच्चे यदि नदी या तालाब चले जाएं और कोई घटना हो जाए, तो उसकी सीधी जवाबदेही प्राचार्य, प्रधान पाठक और शिक्षकों की होगी। स्कूल भवन जर्जर होने से छात्रों को चोट लगने पर भी यही शिक्षक जिम्मेदार माने जाएंगे। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता खराब मिलने पर कार्रवाई शिक्षकों पर होगी। साथ ही बच्चों का आधार आईडी,जाति प्रमाण-पत्र,एसआईआर और स्मार्ट कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों को दी गई है।

आरटीआई कानून को कमजोर करने में लगी हैं सरकारें छत्तीसगढ़ की तरह दूसरे राज्यों में भी हजारों मामले लंबित

रायपुर,10 दिसम्बर 2025। सूचना का अधिकार कानून के तहत रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस दौरान खुलासा हुआ है कि केंद्रीय सूचना आयोग और राज्यों के सूचना आयोगों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। इस वजह से अपीलों की सुनवाई में काफी देरी हो रही है। कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज की याचिका में 1 दिसंबर 2025 को सुनवाई के दौरान पेश की गई तालिका के अनुसार लाखों अपीलें और शिकायतें महीनों-वर्षों से लंबित हैं क्योंकि आयोग ही आधे-अधूरे या पूरी तरह बंद पड़े हैं।

जब केंद्रीय सूचना आयोग का ये हाल तो फिर..

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केंद्रीय सूचना आयोग में 11 में से 9 पद मुख्य सूचना आयुक्त सहित खाली है और यहां 30 हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं। झारखंड में तो सभी 7 पद खाली हैं। मई 2020 से आयोग का दफ्तर ही पूरी तरह बंद है और नई अपीलें तक दर्ज नहीं हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत दोनों पद खाली हैं और जुलाई 2025 से आयोग का कामकाज ठप पड़ा है। छत्तीसगढ़ में मुख्य सहित 3 पद खाली हैं। मुख्य सूचना आयुक्त का पद तो तीन साल से खाली पड़े हैं। 23 नवंबर 2022 से यहां यह पद रिक्त चल रहा है। 30 जून 2025 की स्थिति में राज्य में 34 हजार 147 मामले लंबित हैं। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद राज्य ने अभी तक अतिरिक्त पद स्वीकृत भी नहीं किए हैं। महाराष्ट्र में तो स्थिति और भी गंभीर है। 2019 के फैसले के अनुसार 11 पद होने चाहिए। यहां फिलहाल 11 में से 3 खाली पद हैं और लगभग 90 हजार मामले लंबित हैं। तमिलनाडु में कुछ किया गया है। यहां 7 में से सिर्फ एक पद खाली है, मगर यहां भी 41 हजार 59 मामले लंबित हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य को सूचना आयुक्तों की संख्या बढ़ानी चाहिए। बिहार में 4 में से 1 ही पद रिक्त है और यहां 29 हजार 919 मामले लंबित हैं। यहां भी अधिक पद स्वीकृत करने की जरूरत है। ओडिशा में 7 में से 1 पद खाली है और यहां करीब 20,000 मामले लंबित है। मगर, मध्य प्रदेश में 11 में से 7 पद खाली है और यहां लंबित मामलों की संख्या 18 हजार हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में फिलहाल 8 में से 3 पद खाली चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 8 में से 5 पद खाली हैं।

सीजी में इंटरव्यू के बाद भी नई नियुक्ति नहीं

छत्तीसगढ़ में स्थिति अजीब है। यहां चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इंटरव्यू भी हो चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार नियुक्ति करने की बजाय टालमटोल कर रही है। 17 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि वह दो महीने के अंदर नियुक्ति कर देगी, जबकि इंटरव्यू के बाद सिर्फ चयन सूची जारी करना बाकी है। इसके लिए 60 दिन का समय राज्य सरकार को क्यों चाहिए, यह दाखिल किए गए जवाब से पता नहीं चलता। इस चयन प्रक्रिया को पहले हाईकोर्ट के स्थगन के चलते स्थगित किया गया था पर वह याचिका खारिज हो चुकी है।

सुको के आदेश की अवहेलना कर रही हैं सरकारें

छत्तीसगढ़ में स्थिति अजीब है। यहां चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इंटरव्यू भी हो चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार नियुक्ति करने की बजाय टालमटोल कर रही है। 17 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि वह दो महीने के अंदर नियुक्ति कर देगी, जबकि इंटरव्यू के बाद सिर्फ चयन सूची जारी करना बाकी है। इसके लिए 60 दिन का समय राज्य सरकार को क्यों चाहिए, यह दाखिल किए गए जवाब से पता नहीं चलता। इस चयन प्रक्रिया को पहले हाईकोर्ट के स्थगन के चलते स्थगित किया गया था पर वह याचिका खारिज हो चुकी है।

नायब तहसीलदार पर अवैध धान तस्करी का आरोप,ग्रामीणों ने रात को गाड़ी रोककर विडियो बनाया,फिर... मची खलबली

कवर्धा,10 दिसम्बर 2025। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया जारी है, वहीं दूसरी ओर अवैध धान परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में सख्त निगरानी की जा रही है। इसके बावजूद कबीरधाम जिले में धान तस्करी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, कवर्धा जिले के रेंगाखर क्षेत्र में ग्रामीणों ने देर रात अवैध धान परिवहन करते हुए एक पिकअप और एक मासदा वाहन को रंगे हाथ पकड़ लिया। यह घटना झलमला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीमावर्ती इलाके की बताई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इन वाहनों के जरिए बिना किसी वैध दस्तावेज के धान को राज्य की सीमा पार कराया जा रहा था। ग्रामीणों ने मौके पर उपस्थित नायब तहसीलदार प्रेमनारायण साहू को भी इन वाहनों के साथ देखा,जिससे मामला और अधिक गंभीर हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी की मौजूदगी में ही अवैध धान परिवहन किया जा रहा था, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका गहराती है। बताया जा रहा है कि कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले समनापुर मार्ग पर रात करीब 1 बजे वाहन क्रमांक CG 07 CE 4920 को ग्रामीणों ने रोका। जांच करने पर वाहन में भारी मात्रा में धान भरा हुआ पाया गया। पूछताछ करने पर वाहन चालक विजय बसंत, निवासी ग्राम छपला, थाना बिरसा,जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) कोई भी वैध परिवहन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस दौरान नायब तहसीलदार प्रेमनारायण साहू मौके पर मौजूद थे, जिस पर ग्रामीणों ने अवैध धान परिवहन को उनकी शह पर होने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासनिक अधिकारी ही इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहेंगे, तो अवैध तस्करों के हौसले और बढ़ेंगे।

कार ड्राइवर ने अचानक खोला गेट, बाइक सवार की मौत

बिलासपुर,10 दिसम्बर 2025। कार ड्राइवर ने अचानक गेट खोल दिया, जिससे उसके पीछे आ रहे बाइक युवक टकरा कर गिर गया। इस दौरान सामने से आ रही बाइक युवक के ऊपर से निकल गई। इस हादसे में युवक की मौत हो गई। मुंगेली जिले के ग्राम घुठेली निवासी रूपेश गेंदले मंगला में किराए के मकान में रहता था। वह मैग्नेटो मॉल के पास चाट की दुकान लगाता था। 9 दिसंबर की सुबह वह बाइक से जिम जाने निकला था। अभी वह सर्किट हाउस के पास पहुंचा था। तभी सड़क पर खड़ी कार के चालक ने अचानक गेट खोल दिया। इससे टकरा कर रूपेश बाइक समेत सड़क पर गिर गया। इस दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक सीधे उसके सीने के ऊपर से निकल गई। हादसे में रूपेश को गंभीर चोट आई। तत्काल लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2023-2025-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)